



कमल संदेश

i kml d i f=dk

संपादक

प्रभात झा, सांसद

कार्यकारी संपादक

डॉ. शिव शक्ति बरसी

सहायक संपादक

संजीव कुमार सिन्हा

संपादक मंडल सदस्य

सत्यपाल

कला संपादक

धर्मेन्द्र कौशल

विकास सैनी

सदस्यता शुल्क

वार्षिक : 100/-

त्रि वार्षिक : 250/-

संपर्क

1 nL; rk : +91(11) 23005798

QkU (dk) : +91(11) 23381428

QDI : +91(11) 23387887

पता : डॉ. मुकर्जी सृति न्यास, पी.पी-66,
सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003

ई-मेल

kamalsandesh@yahoo.co.in

प्रकाशक एवं मुद्रक : डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा डॉ.
मुकर्जी सृति न्यास, के लिए एक्सेलप्रिंट, सी-36, एफ.एफ.
कॉम्प्लेक्स, इंडिगालान, नई दिल्ली-55 से मुद्रित करा के,
डॉ. मुकर्जी सृति न्यास, पी.पी-66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग,
नई दिल्ली-110003 से प्रकाशित किया गया। | सम्पादक –
प्रभात झा

विषय-सूची

जनसभाएं

बैंगलुरु (कर्नाटक)..... 7

आगरा (उत्तर प्रदेश)..... 8

विधानसभा चुनाव 2013 पर विशेष

छत्तीसगढ़..... 9

मध्य प्रदेश, दिल्ली..... 10

राजस्थान..... 11

घोषणा-पत्र जारी

मध्य प्रदेश..... 12

राजस्थान..... 13

विशेष साक्षात्कार

श्रीमती वसुधरा राजे, राजस्थान प्रदेश भाजपाध्यक्ष एवं मुख्यमंत्री पद प्रत्याशी 16

लेख

हैदराबाद एक्शन को लेकर नेहरू-पटेल मतभेदों पर डा. के.एम. मुंशी.. 20

- लालकृष्ण आडवाणी.....

मौलाना अबुल कलाम आजाद और आचार्य जेबी कृपलानी की जयंती.. 23

- नरेन्द्र मोदी.....

किसने बदला इतिहास-भूगोल 25

- बलबीर पंज.....

राहुल गांधी का विचित्र मामला 27

- संध्या जैन.....

भारत निर्माण का असली चेहरा

- शशांक द्विवेदी..... 29

मुख पृष्ठ : भाजपा की रैली, बैंगलुरु (कर्नाटक)

स्वतंत्र भारत के
प्रथम गृहमंत्री एवं
उप-प्रधानमंत्री
सरदार वल्लभभाई पटेल
की पुण्यतिथि
(15 दिसंबर) पर



शत-शत
नमन!

बोध कथा

बुद्ध का संदेश

उन दिनों गौतम बुद्ध यात्रा पर थे। रास्ते में उनसे लोग मिलते। कुछ उनके दर्शन करके संतुष्ट हो जाते तो कुछ अपनी समस्याएं रखते थे। बुद्ध सबकी परेशानियों का समाधान करते थे।

एक दिन एक व्यक्ति ने बुद्ध से कहा— मैं एक विचित्र तरह के द्वंद्व से गुजर रहा हूँ। मैं लोगों को प्यास तो करता हूँ पर मुझे बदले में कुछ नहीं मिलता। जब मैं किसी के प्रति स्नेह रखता हूँ तो यह अपेक्षा तो करूँगा ही कि बदले में मुझे भी स्नेह या संतुष्टि मिले। लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं मिलता। मेरा जीवन स्नेह से वंचित है। मैं स्वयं को अकेला महसूस करता हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे व्यवहार में ही कोई कमी है। कृपया बताएं कि मुझ में कहां गलती और कमी है।

बुद्ध ने तुरंत कोई उत्तर नहीं दिया, वे चुप रहे! सब चलते रहे। चलते-चलते बुद्ध के एक शिष्य को प्यास लगी। कुआं पास ही था। रस्सी और बालटी भी पड़ी हुई थी। शिष्य ने बालटी कुएं में डाली और खींचने लगा। कुआं गहरा था। पानी खींचते-खींचते उसके हाथ थक गए पर वह पानी नहीं भर पाया क्योंकि बालटी जब भी ऊपर आती खाली ही रहती। सब यह देखकर हँसने लगे। हालांकि कुछ यह भी सोच रहे थे कि इसमें कोई चमत्कार तो नहीं? थोड़ी देर में सबको कारण समझ में आ गया। दरअसल बालटी में छेद था। बुद्ध ने उस व्यक्ति की तरफ देखा और कहा— हमारा मन भी इसी बालटी की ही तरह है जिसमें कई छेद हैं। आखिर पानी इसमें टिकेगा भी तो कैसे? मन में यदि सुराख रहेगा तो उसमें प्रेम भरेगा कैसे। क्या वह रुक पाएगा? तुम्हें प्रेम मिलता भी है तो टिकता नहीं है। तुम उसे अनुभव नहीं कर पाते क्योंकि मन में विकार रूपी छेद हैं।

संकलन : दीपक कुमार
(नवभारत टाइम्स से साभार)

व्यंग्य चित्र





सुशासन और विकास के लिए भाजपा जरूरी

पाँच च राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। माना जाता है कि ये इस मायने में अत्यंत निर्णायक हो सकते हैं क्योंकि 2014 के आगामी लोकसभा चुनावों पर उनका गहरा प्रभाव पड़ने की उम्मीद जताई जा रही है। छत्तीसगढ़ में भाजपा की खतरे के बावजूद भी लोग भारी संख्या में मतदान करने पहुंचे। मध्य प्रदेश और मिजोरम में 25 नवम्बर को मतदान होगा तो इसके बाद राजस्थान और दिल्ली में चुनावों की बारी आएगी। लोग अपनी सरकारें चुनने की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने के लिए बड़ी संख्या में आ रहे हैं। यह लोकतंत्र की विजय है। सभी 'सर्वेक्षणों' और 'ओपिनियन पोलों' में अभी तक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और दिल्ली में भाजपा की बड़ी जीत की भविष्यवाणियां हुई हैं। लोग यूपीए-नीति सरकार के रिवलाफ वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं क्योंकि लोगों की जनरों में इसकी विश्वसनीयता खत्म हो गई है। जिन राज्यों में भाजपा की सरकारें हैं वहां भाजपा को पहले से भी अधिक जनादेश मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। दिल्ली और राजस्थान में जहां कांग्रेस सरकार का शासन है, वहां भाजपा को इन चुनावों में लोगों का भारी समर्थन मिल रहा है। लोग कांग्रेस के कुशासन और इसके भष्टाचार से मुक्त होना चाहते हैं। देश बड़े बदलाव की ओर बढ़ रहा है क्योंकि लोग पहले से कहीं अधिक संकल्प और दृढ़ता से मतदान करने की तैयारी में जुटे हैं।

आखिर, ऐसा क्यों हो रहा है? वह कांग्रेस, जिसका देश में कभी एक छत्र राज हुआ करता था, वह क्यों हर राज्य से सत्ताच्युत होती जा रही है? अधिकांश बड़े राज्यों में यह अस्तित्वहीन हो चुकी है। बिहार, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, परिचम बंगाल जैसे बड़े राज्यों में इसकी उपस्थित नगण्य है। महाराष्ट्र में, कांग्रेस अपने सहयोगी दलों पर निर्भर है तो आंध्र प्रदेश में इसका पराभव निश्चित होती दिखाई देता है। पूर्वोत्तर क्षेत्रों में भी इसे क्षेत्रीय दलों में गहरी चुनौतियां मिल रही हैं। मध्य प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस लम्बे अरसे से सत्ता से बाहर है और इन राज्यों में इसका संगठनात्मक ढांचा लगभग चरमरा चुका है। ऐसा क्यों हुआ है? इसका प्रमुख कारण है— कांग्रेस का लोकतंत्र पद्धति से गिर कर वंशवाद की प्रवृत्ति में पड़ना। स्वतंत्रता-पूर्व की एक वह कांग्रेस थी जिसमें लोकतांत्रिक भावना थी और उसने महात्मा गांधी और सरदार पटेल जैसी दिग्गज हस्तियों के नेतृत्व में राजनीति के ऊँचे सिद्धांतों को अपनाया हुआ था, परन्तु वह सत्ता में आने पर इन महान विचारों पर खरी नहीं उत्तर पाई। अब कांग्रेस अवसरवादिता और समझौतावाद की राजनीति का प्रमुख केब्ड बन चुकी है। इसने लोकतांत्रिक विचारों और भारत को एक राष्ट्र के रूप में देखने की जगह वंशवाद की राह पर और अधिक तेज रफ्तार से चलना शुरू कर दिया है। कांग्रेस स्वतंत्रता संघर्ष की अपनी विरासत भुला कर केवल एक वंश के हितों की रक्षा करने में जुटी हुई है।

कांग्रेस अब न तो लोकतंत्र का सम्मान करती है और न ही वह इसमें विश्वास करती है। इसका एक मात्र उद्देश्य सत्ता में बने रहना है, चाहे इसके लिए उसे राष्ट्रीय हितों

सुशासन और विकास के
लिए भाजपा जरूरी

की कितनी ही बलि क्यों न देनी पड़े ? 50 वर्षों के अपने निरंतर चल रहे शासन में कांग्रेस ने देश को अंधकार युग में डाल दिया है । हम देखते हैं कि जहां दूसरे देश विकास की राह पर आगे बढ़ते जा रहे हैं, वही भारत अवसरावाद और तुष्टिकरण की राजनीति में डूबा पड़ा है । लोगों को सेक्युलरिज्म के नाम पर गुमराह किया जा रहा है और ऐसे बहुत से समय आए हैं जब इसने राष्ट्रीय हिंतों के साथ समझौता किया है । आज कांग्रेस यदि किसी बात का प्रतीक है तो वह है- भ्रष्टाचार, सिद्धांतविहीन राजनीति, अवसरावादिता और चौतरफा गिरावट । आज इसमें ना तो ‘डायनिज्म’ है ना ही इसके पास नेतृत्व, विजन और विश्वसनीयता है जो देश को आगे बढ़ाने के लिए अत्यावश्यक है । ऐसी परिस्थितियों में भाजपा ही एकमात्र विकल्प रह जाता है । इसके पास विश्वसनीयता, नेतृत्व और भरोसेमंद राजनीति का पुराना रिकार्ड है ।

लोगों का कांग्रेस से मोह भंग हो चुका है और उसके खिलाफ लोगों के मन में कांग्रेसी-विरोधी भाव उभरने से नए-नए संगठन सामने आ रहे हैं जिससे मर्तों का विभाजन हो जाता है । परन्तु इन संगठनों की भी पोल खुलती जा रही है । एक रिटंग आप्रेशन में ख्याल आम आदमी पार्टी (आप) का पर्दाफाश हो गया जिससे पता चलता है इसके दिग्गज नेताओं ने अपने पद का दुर्लभ्योग करते हुए धनराशि लेने में जरा भी हिचक नहीं दिखाई । अब इन नेताओं की

पोल खुल चुकी है । अब कांग्रेस का खेल भी बिंगड़ गया है । एक दूसरी घटना में तहलका के सम्पादक तरुण तेजपाल का अपना यौन-दुराचार ढकने की कोशिश का मामला सामने आया है । आश्चर्य होता है जब हम देखते हैं कि कांग्रेस और ख्याल ‘सिविल सो साइटी’ और तथाकथित प्रगतिशील वर्ग के लोग जैसे तैसे इन सम्पादक महोदय का बचाव करने में जुट गए हैं । परन्तु तरुण तेजपाल को आसानी से छुटकारा नहीं मिल सकता है क्योंकि उनका यह अपराध एकदम जघन्य है । कानून को अपना काम करने देना चाहिए और सम्पादक महोदय को कड़ा दण्ड मिलना चाहिए ।

भारत के लिए समय आ गया है कि हम अपनी खोई गरिमा और महानता फिर से प्राप्त करें । भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह आगे आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए पार्टी को तैयार कर रहे हैं । भाजपा प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार श्री नरेन्द्र मोदी को देश के कोने-कोने से समर्थन मिल रहा है । मध्य प्रदेश में श्री शिवराज सिंह चौहान को भारी समर्थन के साथ पहले से भी जनादेश प्राप्त कर सरकार बनाने की संभावना निश्चित ही है । छत्तीसगढ़ में लोगों ने भारी मतदान कर श्री रमन सिंह की सरकार का पुनः निर्वाचित करने की संभावना भी निश्चित दिखाई पड़ती है । अभी तक मिल रहे संकेतों से श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया राजस्थान में सरकार बनाएंगी और कांग्रेस को चुनावों

में हार का सामना करना पड़ेगा । दिल्ली में डा. हर्षवर्धन की बेदाग छवि के कारण भाजपा सरकार बनाने की स्थिति पहुंच गई है । इन परिणामों से स्पष्ट ही 2014 के आगामी लोकसभा चुनावों की राह सामने दिखाई पड़ने लगी है । भाजपा के पास नेतृत्व, विश्वसनीयता, नीतियां और कार्यक्रम है जिनसे भारत एक विकसित राष्ट्र बनेगा । लोग अभी तक भी श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में बनी एनडीए सरकार द्वारा शुल्क की गई राष्ट्र-निर्माण परियोजनाओं को भूले नहीं हैं । कांग्रेस-नीति यूपीए सरकार ने विकास की गति में रुकावट डाली है ।

भाजपा फिर से उस गति को पाने का संकल्प कर चुकी है और केंद्र में श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में और भी ऊंचे शिखर को छूने के लिए प्रतिबद्ध है । राज्यों में भाजपा सरकारों ने अपने अथक प्रयासों से जबरदस्त विश्वसनीयता अर्जित की है जिसके अभूतपूर्व परिणाम मिल रहे हैं । अब भाजपा कार्यकर्ताओं का कर्तव्य बनता है कि वे आने वाले महीनों में अथक प्रयास कर सुनिश्चित करें कि भारत के हिंतों के साथ किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा और मां भारती को परम वैभव प्राप्त होगा जिसके प्रति हम सभी लोग प्रतिबद्ध हैं । अब हमें रुकावा नहीं है... अब हमें आगे... और आगे बढ़ते चले जाना है ताकि हम राष्ट्र का नेतृत्व कर विकास, समृद्धि और महान गौरव के नए युग को ला सकें । ■

जनसभाएं

बैंगलुरु (कर्नाटक)

देश से भ्रष्टाचारी शासन को उखाड़कर ईमानदार सरकार दी जाए : नरेन्द्र मोदी



भा जपा की ओर से प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस को उनकी लोकप्रियता और रैलियों में आ रही भीड़ हजम नहीं हो रही है। इसी बजह से उनके खिलाफ साजिश रच रही है। श्री मोदी ने 17 नवम्बर को बैंगलुरु के पैलेस मैदान में रैली को संबोधित करते हुए उक्त बातें कहीं।

श्री मोदी ने इस दौरान कांग्रेस पर लोकतंत्र का गला घोंटने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि जिसने भी उनके पक्ष में बोला, उसे कांग्रेस ने निशाना बनाया। फिर चाहे वह लता मंगेशकर हो या ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म। श्री मोदी ने कहा, ‘इन दिनों भाजपा पर हमले बढ़ गए हैं। श्री नरेंद्र मोदी पर हमले भी बढ़ गए हैं। हमले इस नजरे (भीड़ की ओर से इशारा करते हुए) की बजह से बढ़े हैं। वे यह पचा नहीं पा रहे हैं। न जाने किस तरह की भाषा बोली जा रही है। साजिशों रची जा रही हैं। वे किसी न किसी तरह से भाजपा को बदनाम करना चाहते हैं।’

श्री मोदी ने कहा कि इन दिनों नीचे गिरने की स्पर्धा चल रही है। रुपए की कीमत नीचे जाएगी या यूपीए की आबरू? लगता है कि यूपीए का रूपया आईसीयू में पड़ा है। मोदी ने हल्के-फुल्के अंदाज में कहा, ‘जब पूरा देश सचिनमय हो गया था, तब वानखेड़े में बैठे लोग चर्चा कर रहे थे। कह रहे कि बताओ, सचिन सेंचुरी लगाएंगे या प्याज के दाम?

श्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की तारीफ के पुल बांध दिए। श्री मोदी ने आईटी क्षेत्र में विकास का श्रेय भी वाजपेयी को दिया।

उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने ही मून मिशन की घोषणा की थी। जो 2008 में सफल रहा था। मंगल यात्रा भी वाजपेयी की ही देन है।

श्री मोदी ने कहा कि अब संप्रग सरकार की विदाई का समय आ गया है। वैसे भी यूपीए सरकार बहुमत के बल पर सत्ता में नहीं है बल्कि सीबीआई के दम पर सत्ता का सुख भोग रही है। अब समय आ गया है कि देश से भ्रष्टाचारी शासन को उखाड़कर ईमानदार सरकार दी जाए। ■

आगरा (उत्तर प्रदेश)

देश को दीमक की तरह चाट रही कांग्रेस

ग

त 21 नवम्बर को आगरा में आयोजित विशाल जनसभा में श्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर एक साथ हमला बोला। कांग्रेस को दीमक की संज्ञा दी तो सपा पर उत्तर प्रदेश के विकास में कोई रुचि न लेने और जनसमस्याओं की अनदेखी का आरोप जड़ा। अपने अंदाज के मुताबिक विशाल जनसमूह से संवाद स्थापित करते हुए श्री मोदी ने बोट बैंक की राजनीति के लिए सपा और बसपा को भी आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि दोनों दल राजनीति के इस कांग्रेसी तरीके को अपने रंग में रंगकर एक-दूसरे को पीछे छोड़ने में लगे हैं।

श्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस दीमक की तरह देश को चाट रही है। उसने अपनी विघटनकारी नीतियों और भ्रष्ट आचरण से देश को बर्बादी के कगार पर खड़ा कर दिया है। जनता भाजपा के हाथ सत्ता सौंपे जिससे वह देश को विकास और समृद्धि के रास्ते पर ले जा सके। कांग्रेस को निशाने पर रखते हुए श्री मोदी ने उसे अहंकारी और मोटी खाल वाला बताया, जो लोगों की अपेक्षाओं की परवाह नहीं करती है। श्री मोदी ने कहा कि दिल्ली की कांग्रेस को देश की तरकी से वास्ता नहीं है। वह देश की तकदीर बदलने में विश्वास नहीं रखती। वह केवल बोट बैंक की राजनीति करती है। उसे जोड़तोड़ की राजनीति में भरोसा रहता है। इसीलिए वह 25 फीसद लोगों को साथ लेकर चलती है और 75 फीसद की अनदेखी करती है। कांग्रेस के विघटनकारी होने को परिभाषित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सत्ता के लिए वह इस नीति पर चलती है। स्वतंत्रता के समय सत्ता के लिए कांग्रेस ने देश को तोड़ा। उसने वंदे मातरम् को बांटा। कश्मीर में अलग कानून की अनुमति दी, ..और उसके बाद पानी, भाषा, उत्तर-दक्षिण और शहरी-ग्रामीण के नाम पर लोगों को बांटा।

बोट बैंक की राजनीति के मामले में सपा और बसपा को कांग्रेस जैसा ही बताते हुए श्री मोदी ने कहा इससे देश जर्जर हो रहा है-उसका नुकसान हो रहा है। देश को विकास की जरूरत है। देश को एकजुट रखते हुए तरकी की राह पर भाजपा ही ले जा सकती है, इसलिए लोग उसे मजबूत करें। श्री मोदी ने सत्ता में आने पर देश के एक करोड़ युवाओं को रोजगार मुहैया कराने का वादा किया।

श्री मोदी ने कहा, एक केंद्रीय मंत्री और उनके परिवार द्वारा चलाए जा रहे गैर सरकारी संगठन ने 70 लाख रुपये के व्यय में गड़बड़ी की। एक अन्य केंद्रीय मंत्री ने बचाव में आकर सफाई दी, 70 लाख कुछ नहीं होते, अगर मामला 70 करोड़ का होता तो वह विश्वास करते कि गड़बड़ी में केंद्रीय मंत्री शामिल होगा।

श्री मोदी ने आगरा की पेयजल की समस्या और अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा न होने की बात भी उठाई। उन्होंने



कहा कि प्रदेश सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। विकास से उसका कोई लेना-देना नहीं है।

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह ने दीन दयाल उपाध्याय और अटल जी की जन्मस्थली के बीच बसे आगरा की जनता को नमन करके अपने भाषण को आरंभ किया। उन्होंने प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार पर कटाक्ष करते हुए बोला कि सपा और बसपा ने उत्तर प्रदेश को लूटा और कांग्रेस सरकार ने पूरे हिंदुस्तान को लूटा है।

उन्होंने कहा कि यदि मोदीजी प्रधानमंत्री बनते हैं तो खेतों में बुवाई से पहले ही फसल की आमदनी तय हो जाएगी। और साथ ही अगर फसल नष्ट हुई तो बीमा कंपनियां फसल का भुगतान देंगी। कांग्रेस ने पूरे विश्व में भारत की छवि खराब कर दी है लेकिन भाजपा छवि सुधारेगी। उन्होंने कहा कि चीन और पाकिस्तान आंख उठाकर भी भारत की ओर देखने की जुरत नहीं करेंगे।

उन्होंने कहा कि परिवर्तन की लहर चल चुकी है और इसमें युवाओं की अधिक जिम्मेदारी बनती है। उ.प्र. की 80 में 80 सीटों को भाजपा की झोली में डाल दो। ■

विधानसभा चुनाव-2013 : प्रचार पर विशेष

पांच राज्यों-मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, दिल्ली और मिजोरम-के विधानसभा चुनाव प्रचार जोरों पर हैं। प्रधानमंत्री पद के लिए भाजपा प्रत्याशी श्री नरेंद्र मोदी विभिन्न राज्यों में भाजपा की ओर से आयोजित जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। उनकी सभाओं में लाखों लोग उन्हें सुनने आते हैं। विशाल जनसमूह से संवाद स्थापित करते हुए श्री मोदी देश में व्याप्त अराजकता के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराते हैं और कांग्रेसमुक्त भारत बनाने का आहवान करते हैं। इसके साथ ही वे लोगों से इन सभी राज्यों में विकास और सुशासन के लिए कमल खिलाने की अपील करते हैं। हम यहां प्रमुख जनसभाओं के समाचार प्रकाशित कर रहे हैं :

छत्तीसगढ़

**जितना ज्यादा कीचड़ उठालोगे
उतना ही ज्यादा कमल खिलेगा : नरेंद्र मोदी**



भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की बिंगड़ी हुई व्यवस्था के लिए नेहरू, इंदिरा और राजीव गांधी जिम्मेदार हैं।

श्री मोदी ने 15 नवम्बर को रायगढ़ में आयोजित एक छत्तीसगढ़ में कहा कि भारत की मौजूदा व्यवस्था को बनाने वाले, बिगड़ने वाले और इसकी गुनहगार भी कांग्रेस है। श्री मोदी ने कहा कि शहजादे ने कहा कि वे व्यवस्था बदलना चाहते हैं, लेकिन यह व्यवस्था किसकी देन है? पिछले 60 साल में यह व्यवस्था किसने बनाई है शहजादे? आपके पिता, आपकी दादी और आपके नाना ने यह व्यवस्था बनाई और

निहित स्वार्थों के कारण इसे नष्ट कर दिया। छत्तीसगढ़ की चुनावी सभा में श्री मोदी ने कहा कि राज्य को जो पैसा केंद्र से मिलता है वह क्या 'शहजादे के मामा' के यहां से आता है।

उन्होंने कहा कि शहजादे से पूछिए कि इस प्रदेश को जो 10 हजार करोड़ रुपए मिले हैं, वो उनके मामा के यहां से आए हैं। श्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस यह भी नहीं जानती कि केंद्र में सरकार कैसे चलाना है? सरकार में काम क्या करना है? जनहित में क्या निर्णय लेना है क्योंकि पूरी सरकार इस काम में व्यस्त है कि मोदी क्या कर रहा है? मोदी क्या बोल रहा है? श्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस मोदी पर जितना ज्यादा कीचड़ उठालेगी, उतना ही ज्यादा कमल खिलेगा। क्योंकि कमल हमेशा कीचड़ में ही खिलता है। उन्होंने कहा कि पशुपति से तेरूपति तक नक्सलवाद, सीमा पर गोलीबारी और देश की सुरक्षा के मामले में केंद्र सरकार पूरी तरह से असफल रही है। श्री मोदी ने कहा कि सोनिया गांधी ने आतंकवाद के खिलाफ बनाए गए पोटा कानून को समाप्त कर हिंसक तत्वों को खुला मैदान दे दिया है। आतंकवाद और नक्सलवाद से लड़ने की जिम्मेदारी केंद्र की है और मैडम आरोप लगाती हैं कि छत्तीसगढ़ में रमन सरकार में नक्सलवाद बढ़ा है। उन्होंने मीडिया पर दोहरे मापदंड का आरोप लगाया और कहा कि मीडिया की मेहरबानी से कांग्रेस और उसके आका बचे हुए हैं। मीडिया जो सवाल मुझसे करती है वह उसे नहीं करती है।

केंद्रीय मंत्री और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष की ओर से दिए गए बयान पर कि रमन सरकार पैसे देकर अवार्ड लेती है, श्री मोदी ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि पैसे लेने वाले कौन हैं। यदि प्रधानमंत्री ने अवार्ड दिया है तब पैसे किसने लिए? श्री मोदी ने कहा कि देश और जनता को कांग्रेस पर, उनकी बातों पर, उनके नेताओं पर, उनके वादों

पर, उनकी नीतियों पर और उनकी नीयत पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। मशहूर गायिका लता मंगेशकर की ओर से हाल ही में श्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करने पर कांग्रेस नेताओं की उनका भारत रत्न सम्मान वापस करने की मांग को लेकर उन्होंने कहा कि यह कांग्रेस का हिटलरशाही और फासीवाद रखैया है। उन्होंने लोगों से कहा कि वे महात्मा गांधी की उस इच्छा को अवश्य पूरा करें, जिसमें उन्होंने कहा था कि अब कांग्रेस का समय पूरा हो गया है, इसकी जरूरत नहीं है।

मध्यप्रदेश

केन्द्र की संप्रग सरकार मात्र 200 दिन की मेहमान

केन्द्र की संप्रग सरकार को मात्र 200 दिन की मेहमान बताते हुए श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि यदि केन्द्र और मध्यप्रदेश दोनों में भाजपा की सरकार होगी, तो राज्य का विकास तेजी से होगा।

श्री मोदी ने 18 नवम्बर को छतरपुर, सागर, गुना एवं



भोपाल की सभाओं को संबोधित करते हुए कहा, मात्र 200 दिन बाद केन्द्र में भी भाजपा की सरकार

बनने वाली है और यदि प्रदेश की जनता यहां लगातार तीसरी बार पार्टी को चुनेगी, तो उसके दोनों हाथों में लड्डू होंगे।

उन्होंने केन्द्र सरकार पर प्रदेश में भाजपा की सरकार होने की वजह से विकास में रोड़े अटकाने का आरोप लगाते हुए कहा कि इसलिए राज्य से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत नहीं होती और विकास के कामों में अड़ंगे डाले जाते हैं। श्री मोदी ने कहा कि वह यहां शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनाने या भाजपा को जिताने का आह्वान करने नहीं आए हैं। उन्होंने दावा किया कि यहां तो भाजपा जीत ही रही है, वह यहां जीत की गंगा में पुण्य कमाने आए हैं। यहां शिवराज सरकार ने

जनता का विश्वास जीता है। अब तो विजय, विकास की राजनीति ही होगी। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में जिन्होंने पहले सरकारें चलाई हैं, क्या उन्होंने कोई अच्छा काम किया है। यहां उन्होंने केवल बंटाढार किया है। इसका सबसे बड़ा कारण कांग्रेस की मानसिकता और अहंकार है। वह देश को अपनी जागीर मानती है।

दिल्ली

कांग्रेस की नीतियां केवल चुनाव केन्द्रित उसे देशहित से सरोकर नहीं

श्री नरेंद्र मोदी ने 23 नवम्बर को दिल्ली में कांग्रेस पार्टी पर उसके 'अहंकार' और 'सत्ता के लिए ही जन्म लेने की' मानसिकता पर प्रहर करते हुए उस पर देश के लिए नहीं बल्कि केवल चुनाव जीतने की नीतियां बनाने का आरोप लगाया। चार दिसंबर को होने जा रहे दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले यहां द्वारका क्षेत्र में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा



के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार ने कहा कि कांग्रेस ने अक्सर अपना नाम, चिह्न और नीतियां बदलीं लेकिन अपनी नीयत नहीं बदली।

उन्होंने कहा, कांग्रेस पार्टी यह मान बैठी है कि ईश्वर ने उसे शासन करने के लिए ही बनाया है। वे सोचते हैं कि उनका जन्म ही शासन करने के लिए हुआ है और जनता तो उनकी जेब में है। वह (जनता) जाएगी कहां, कभी-कभी वे उन्हें मोदी का डर दिखाती हैं और बोट पाती हैं। कांग्रेस के लोगों शासन करने का चस्का लग गया है। उन्होंने कहा, उसकी सारी नीतियों चुनाव जीतने पर केंद्रित होती हैं न कि राष्ट्र के लिए और न ही उसके भविष्य के लिए। कांग्रेस में यदि कुछ नहीं बदला, तो यह उनकी

नीयत है। उनकी नीयत ऐसी है, उस नीयत को लेकर देश का भला नहीं हो सकता।

श्री मोदी ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर भी वार किया और उन पर गरीबी और आम आदमी पर बुरा असर डालने वाली महंगाई पर एक भी शब्द नहीं बोलने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में मुद्रास्फीति 3.9 फीसदी थी। अब एक अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री के अंतर्गत यह 11 फीसदी से अधिक है। यदि महंगाई इस कदर बढ़ती रही तो गरीब खाएंगे क्या? प्रधानमंत्री महंगाई का ठीकरा अपने सिर पर लेने को तैयार नहीं हैं। कांग्रेस पर 'अहंकार' का आरोप मढ़ते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने आज की रैली में देर से पहुंचने के लिए माफी मांगी लेकिन प्रधानमंत्री महंगाई की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है।

श्री मोदी ने कहा, उनका अहंकार इतना है, महंगाई पर एक शब्द भी बोलने को तैयार नहीं हैं। महंगाई का 'म' तक नहीं बोले। मरो तो मरो- आपका नसीब। उन्होंने शीला दीक्षित सरकार पर भी करारा प्रहर किया और कहा वह विकास के गुजरात मॉडल पर तो सवाल खड़ा करती है लेकिन क्या 15 साल सत्ता में रहने के बाद भी राजधानी के निवासियों को, यहां तक मूलभूत जरूरत पैयजल तक भी दे पाई हैं?

श्रीमती शीला दीक्षित पर कटाक्ष करते हुए श्री मोदी ने कहा कि वह अपने बेटे और बहू के साथ गुजरात के 9000 गांवों में पानी प्रदान करने के लिए बिछी लंबी पाइपलाइन में अपनी मारुति कार चला सकती हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस महान पार्टी है। उसका नाम बदल गया, चिह्न बदल गया और उसकी नीतियां भी बदल गई। आज बाजार में उसके दर्जनों नाम हैं। उन्होंने कहा, उसका चिह्न भी बदल गया और इसलिए नीतियां भी बदली। उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर चुनाव जीते। तब नरसिंहा राव आए और उन्होंने चुनाव जीतने के लिए सुधार की नीति शुरू की।

राजस्थान

बंटवारे का फलसफा कांग्रेस के डीएनए में शामिल

श्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को "फूट डालो और राज करो" की नीति पर अमल करने वाली पार्टी करार दिया। श्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस हिन्दू-मुसलमानों के बीच तनाव बढ़ाकर राज करती रही है, बंटवारे का फलसफा सौ साल पुरानी इस पार्टी के डीएनए में शामिल है।

सवाई माधोपुर, अलवर, बांदीकुई, भरतपुर में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में धुआंधार प्रचार करते श्री मोदी ने कांग्रेस और राहुल पर जमकर निशाना साधा। सवाई माधोपुर



में पार्टी उम्मीदवार दीया कुमारी के प्रचार अभियान को धार देते श्री मोदी ने कांग्रेस को विभाजनकारी मानसिकता से ग्रस्त बताया। उन्होंने कहा कि इसका काम मतभेद की दीवार ऊंची कर एक भाई को दूसरे भाई से लड़ाना है। अब इसके चरित्र, संस्कृति, परम्परा व सोच को पहचानने का वक्त आ गया है। कांग्रेस के लोग कभी भी समाज को एकजुट रखने के बारे में नहीं सोचते। वह केवल तोड़ना जानते हैं, यही उनकी शैली है। कांग्रेस ने हमेशा उत्तर दक्षिण, हिंदी-मुस्लिम के बीच मतभेद पैदा किए हैं। इससे एक बात साबित होती है कि यह बोट बैंक की राजनीति करने वाली पार्टी है।

अलवर और बांदीकुई की चुनावी सभाओं में श्री मोदी ने राहुल गांधी की दिल्ली में आयोजित चुनावी सभा में भीड़ न जुटने पर चुटकी ली। उन्होंने अलवर रैली में जुटी विशाल भीड़ की तरफ देखकर कहा कि कुछ ऐसी भी रैलियां होती हैं जहां लोगों को हाथ जोड़कर रुकने के लिए मिनटों करनी पड़ती हैं। उनसे कहना पड़ता है कि वह पार्टी के नेता को सुनकर जाएं। इसके उलट कुछ रैलियां ऐसी हैं जहां लोगों को खड़े होने तक की जगह नहीं मिलती और उन सबसे माफी मांगनी पड़ती है जो उन्हें देख तक नहीं पाते। श्री मोदी का इशारा दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित की तरफ था जिन्हें 17 नवंबर को राहुल के आने तक भीड़ को रोके रखना कठिन हो गया था। मुट्ठी भर लोगों की इस सभा में मजबूरन कांग्रेस उपाध्यक्ष को मात्र छह मिनट में अपना भाषण खत्म करना पड़ा था। बांदीकुई में महंगाई का मुद्दा उठाते भाजपा नेता ने कहा कि घमंड में चूर कांग्रेस सरकार बढ़ती कीमतों पर लगाम कसकर आम जनता को राहत देने की कोई कोशिश नहीं कर रही। इसी तरह भ्रष्टाचार के मामलों में भी संप्रग सरकार का कोई कोशिश सानी नहीं। उसने नभ, जल और थल में भ्रष्टाचार का कोई कोना नहीं छोड़ा। उसे विदेशों में जमा काला धन देश वापस लाने की भी कोई चिंता नहीं। ■

मध्य प्रदेश

युवाओं को स्मार्टफोन, गरीबों को चावल

म

ध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा द्वारा जारी घोषणा-पत्र में सरकारी कॉलेजों में प्रवेश लेने वालों को स्मार्ट फोन, प्रतिभाशाली युवाओं को लैपटॉप, गरीबों को गेहूं के समान ही एक रुपए किलो चावल देने, गरीबों, किसानों एवं भूमिहीनों के लिए 15 लाख आवास बनाने एवं किसानों के लिए नई फसल बीमा योजना बनाने का वायदा किया गया है।

इसमें युवाओं की ओर विशेष ध्यान दिया गया गया है। भाजपा ने सरकारी कॉलेजों में प्रवेश लेने वालों को स्मार्ट फोन देने के साथ ही प्रतिभाशाली युवाओं को लैपटॉप, 10 से 15 किलोमीटर तक की दूरी से आने वाली छात्राओं को बसों में शैक्षणिक पास, तथा दिन प्रति दिन मंहगी होती जा रही उच्च शिक्षा हेतु शुल्क ढांचे के पुनर्निर्धारण का वायदा शामिल है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि मध्यप्रदेश में जहां प्रशासनिक



गत 16 नवम्बर को भोपाल में लोकसभा में विपक्ष की नेता श्रीमती सुषमा स्वराज, भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री श्री अनंत कुमार, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री नरेंद्र सिंह तोमर, म.प्र भाजपा की चुनाव प्रबंध समिति के संयोजक श्री अनिल माधव दवे, प्रदेश घोषणा पत्र समिति के संयोजक श्री विक्रम वर्मा ने अन्य भाजपा नेताओं की उपस्थिति में घोषणा-पत्र जारी करते हुए कहा कि यह घोषणा पत्र नहीं, बल्कि एक जन संकल्प है। यह भाजपा की विकास के प्रति प्रतिबद्धता, समाज के कमज़ोर वर्गों के कल्याण के प्रति समर्पण और मध्यप्रदेश की जनता की सेवा का निश्चय है।

मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान ने इस अवसर पर घोषणा पत्र में किए गए वायदों का जिक्र करते हुए कहा कि

कृषि पर समग्रता से विचार योजना निर्माण, क्रियान्वयन व विभिन्न प्रबंधन करने के लिए पृथक् कृषि बजट के साथ ही किसानों के कर्जों को आवश्यक परिस्थितियों में माफ करने के लिए मप्र ऋण राहत आयोग बनाया जाएगा, जो अलग-अलग जिलों के लिए अवार्ड घोषित करेगा और परिस्थिति अनुसार ऋण राहत योजनाएं अनुशंसित करेगा।

सुधार आयोग का गठन किया जाएगा, वहाँ अंत्योदय मेलों से आगे जाकर चिह्नित शासकीय सेवाओं की होम डिलीवरी की जाएगी। साथ ही जिला पुनर्गठन आयोग का गठन किया जाएगा और कक्षा दसर्वी के परीक्षा परिणाम के साथ ही जाति प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि कृषि पर समग्रता से विचार योजना निर्माण, क्रियान्वयन व विभिन्न प्रबंधन करने के लिए पृथक् कृषि बजट के साथ ही किसानों के कर्जों को आवश्यक परिस्थितियों में माफ करने के लिए मप्र ऋण राहत आयोग बनाया जाएगा, जो अलग-अलग जिलों के लिए अवार्ड घोषित करेगा और परिस्थिति अनुसार ऋण राहत योजनाएं अनुशंसित करेगा।

उन्होंने कहा कि इसके साथ ही जहां खेतीहर मजदूरों के

लिए भविष्य निधि योजना आरंभ की जाएगी, वहीं मुख्यमंत्री खेत सड़क योजना भी शुरू की जायेगी। साथ ही पशुओं के लिए चलित उपचार सेवा 109 शुरू की जाएगी।

श्री चौहान ने कहा कि जो गांव-सड़कों से नहीं जुड़ पाए हैं, उन सभी को अगले पांच वर्षों में सड़क सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही ग्रामीण हाट बाजारों को स्थानीय करों से मुक्ति दी जाएगी। नारी शक्ति का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि शिक्षित महिलाओं को उद्योग एवं व्यापार हेतु रियायती दर पर ऋण, अचल सम्पत्ति एवं भूमि की रजिस्ट्री में स्टांप शुल्क में महिलाओं को विशेष छूट, महिलाओं के नाम पर वाहन पंजीयन में विशेष रियायत तथा महिलाओं को ड्राइविंग लाइसेंस शुल्क से मुक्ति दी जाएगी।

उद्योगों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि म.प्र. में खुदरा में बहु ब्रांड को एफडीआई की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने कहा कि भोपाल-इंदौर, भोपाल-बीना, जबलपुर-सिंगारोली एवं मुरैना निवेश गलियारा परियोजना का क्रियान्वयन शुरू किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2003-04 में विद्युत का उत्पादन

4673 मेगावाट था जो वर्ष 2013 में बढ़कर 10517 मेगावाट हो गया है तथा वर्ष 2020 तक इसे बढ़ाकर 20 हजार मेगावाट किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि इसी प्रकार वर्ष 2003-04 के सात लाख हेक्टेयर के मुकाबले सिंचाई क्षमता 25 लाख हेक्टेयर कर दी गई है और अब इसे बढ़ाकर 75 लाख हेक्टेयर तक किया जाएगा।

श्री चौहान ने कहा कि अगले पांच सालों में प्रदेश में जहां पांच स्थानों पर सरकारी मेडिकल कॉलेजों खोले जायेंगे वहीं मेडिकल सीटों को 2018 में वर्तमान 1620 से बढ़ाकर पांच हजार तक करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

पत्रकारों की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी राज्यस्तरीय अधिमान्य पत्रकारों को लैपटॉप, पत्रकारों की कठिनाईयों के अध्ययन एवं निराकरण हेतु समिति, पत्रकारों को आवासीय भूखंड एवं रियायती दर पर आवासीय ऋण हेतु नीति एवं कार्यक्रम के साथ ही पत्रकारों के लिए सामूहिक बीमा योजना लागू की जाएगी। ■

राजस्थान

5 लाख लोगों को रोजगार देने का वादा



राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने चुनाव घोषणा पत्र में 15 लाख व्यक्तियों को रोजगार देने, अध्यापक पात्रता परीक्षा (टेट) की समीक्षा करने, 1500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने, 1 प्रतिशत पर कृषि ऋण तथा 3 प्रतिशत पर बेरोजगारों को 20 लाख

रुपए की गारंटी देने का वादा किया है।

गत 20 नवम्बर को जयपुर में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह ने घोषणा पत्र (सुराज संकल्प पत्र) का लोकार्पण किया। इस अवसर पर प्रदेश भाजपा प्रभारी श्री कप्तान सिंह सोलंकी, पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे,

प्रतिपक्ष के नेता श्री गुलाबचंद कटरिया सहित कई नेता मौजूद थे।

संकल्प पत्र में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए स्थायी तंत्र स्थापित करने, फसल के नुकसान का आकलन ग्राम पंचायत से करने, तारबंदी का अनुदान देने, नई फसल बीमा नीति बनाने, खजूर तथा ओलीव्ज की खेती को बढ़ावा देने, कृषि क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने का वादा भी किया गया है।

इसी तरह गौपालन मंत्रालय तथा कामधेनु विश्वविद्यालय की स्थापना करने, गौ तस्करी कानून की समीक्षा करने, गौवंश को राज्य धरोहर, ऊंट तथा मोर राज्य धरोहर घोषित करने, मंदिर माफी की भूमि प्रबंधन करने, प्रत्येक जिले में चारा बैंक

घोषणा पत्र में 15 लाख व्यक्तियों को रोजगार देने, अध्यापक पात्रता परीक्षा (टेट) की समीक्षा करने, 1500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने, 1 प्रतिशत पर कृषि ऋण तथा 3 प्रतिशत पर बेरोजगारों को 20 लाख रुपए की गारंटी देने का वादा किया है।

तथा भेड़-बकरियों को राज्य आपदा प्रबंध योजना में शामिल करने की बात कही गई है।

सुराज संकल्प पत्र में ग्राम पंचायत एवं पंचायत समितियों को पुर्णांगित करने के लिए आयोग बनाने, ग्राम पंचायतों में पुराने घरों को आवासीय पट्टे दिलाने, एपीएल परिवारों को सस्ता आटा देने, पंचायत राज के निर्वाचित सदस्यों का मानदेय बढ़ाने का वादा किया गया है।

इसी तरह 24 घंटे घरेलू बिजली तथा सिंचाई के लिए 8 घंटे श्री फेस बिजली देने, बूंद-बूंद सिंचाई योजना में दिए गए कनेक्शनों को साधारण कनेक्शन मानने, निःशुल्क मीटर बदलने, चम्बल योजना को बिसलपुर योजना से जोड़ने, पर्याप्त स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने, वर्षा के पानी को रोककर विस्तार सिंचाई योजना बनाने, नदियों को जोड़ने का विश्वास दिलाया गया है।

सड़क परिवहन के तहत भाजपा ने सड़क सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कानून में संशोधन, बस अड्डा प्राधिकरण बनाने, सड़कों का उच्चीकरण, एयर टैक्सी सर्विस लागू करने की बात कही गई है।

शिक्षा प्रणाली में सुधार का वादा करते हुए भाजपा ने प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रमों में बदलाव करने, महिला

विश्वविद्यालय एवं शिक्षक प्रशिक्षण विश्वविद्यालय के साथ सरकारी एवं गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं के संचालन के लिए नियामक बोर्ड का गठन करने, द्वोणाचार्य आवासीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की स्थापना करने, दोपहर भोजन योजना को मजबूत करने, लैपटॉप टेबलेट उपलब्ध कराने की योजना व्यावहारिक बनाने का वादा किया गया है।

इसी तरह ए क्लास आयुष चिकित्सालयों में लैब टेक्नीशियन लगाने, निःशुल्क दवा एवं निःशुल्क जांच की समीक्षा कर गुणात्मक सुधार लाने, छात्राओं के नियमित स्वास्थ्य परीक्षण एवं टीकाकरण करने का वादा किया गया है।

भाजपा ने सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन विसंगति को दूर करने के लिए उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन करने, चयनित वेतनमान के मामले में उच्च स्तरीय समिति का गठन करने, ग्रामीण कर्मचारियों को भत्ता देने के साथ मकान किराए में बढ़ोतरी देने का वादा किया गया है।

संकल्प पत्र में अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के रिक्तियों के बैकलॉग को समयबद्ध तरीके से भरने, अम्बडेकर स्वायत्त केंद्र बनाने, आदिवासी बोलियों के संरक्षण, हाड़ी रानी बटालियन की तर्ज पर महाराणा पुलिस बटालियन का गठन करने का वादा किया गया है।

विशेष पिछड़ा वर्ग में सम्मिलित गुर्जर, रायका, रैबारी, बंजारा, बालदिया, लवाना, गाड़िया लोहार को 5 प्रतिशत आरक्षण प्रावधान संविधान की नौवीं सूची में सम्मिलित कराने के लिए कार्रवाई करने, देवनारायण योजना में अतिरिक्त बजट के लिए प्रावधान, कर्मकांड ज्योतिष आयुर्वेद की शिक्षा प्राप्त करने के लिए आदिशंकराचार्य बोर्ड गठित करने, भगवान परशुराम विश्वविद्यालय गठित करने का वादा किया गया है।

भाजपा ने अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए शिक्षा में प्रवेश के लिए प्रोत्साहन देने, व्यवसाय के लिए रियायती दर पर ऋण देने, मदरसों का आधुनिकीकरण करने का वादा किया गया है।

संकल्प पत्र में पत्रकारों के लिए लागू मेडिकलेम पॉलिसी को कैशलैस करने तथा इस सुविधा को 10 लाख तक बढ़ाने, इसमें पत्रकार के आश्रित परिजनों को शामिल करने तथा अधिवक्ताओं के लिए ई-लाईब्रेरी की आधारभूत सुविधा स्थापित करने, जिला स्तर पर वकीलों के आवास के लिए ग्रुप हाउसिंग योजना को व्यावहारिक बनाने का वादा किया गया है। ■

छत्तीसगढ़

कांग्रेस ने जनता के भरोसे को तोड़ा है : राजनाथ सिंह

भा जपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत को दुनिया के उच्च शिखर पर बैठाना ही हमारा लक्ष्य है। पिछले कुछ वर्षों में केंद्र की कांग्रेस गठबंधन सरकार ने भारत के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाते हुए देश को गर्त में ढकेला है। देश में कांग्रेस ने भ्रष्टाचार और घोटाले कर विश्व रिकार्ड बनाया है। जनता से वादाखिलाफी करते हुए महंगाई को चरम पर पहुंचा दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने देश के भरोसे

है कि कांग्रेस की सरकार बनी तो प्रधानमंत्री कौन होगा लेकिन कांग्रेसी नाम सामने करने से डर रहे हैं।

कांग्रेस मुद्दों के अभाव में भाजपा पर अनर्गल और बेबुनियाद आरोप लगाते हुए कांग्रेस के लोग सिर्फ हल्ला करते हुए जनता को गुमराह करने में लगी है। देश की जनता को कांग्रेस के अनर्गल और बेबुनियाद आरोपों से प्रभावित होने वाली नहीं।

कांग्रेस द्वारा मोदी जी के बारे में पुनर्विचार करने के सुझाव के बारे में पूछे

जाने पर उन्होंने दो टूक कहा कि मोदी को लेकर भाजपा टूट है और पुनर्विचार करने का कोई प्रश्न नहीं उठता। कांग्रेस जितने भी अनर्गल और बेबुनियाद आरोप लगाएगी भाजपा उतनी ही शक्तिशाली होकर उभरेगी।

उन्होंने कांग्रेस के लोगों से अपील की कि

विधानसभा और लोकसभा चुनाव स्पष्ट माहौल में होने दीजिए। किसी भी परिस्थिति में मर्यादाएं नहीं टूटनी चाहिए। कांग्रेसी जिस तरह से मर्यादाएं तोड़ रहे हैं उससे स्पष्ट है कि कांग्रेसी अभी से अपनी हार मान चुके हैं। कांग्रेस के नेता देश - प्रदेश में अपनी मर्यादाओं को तोड़ रहे हैं। मैं देश की जनता से अपील करता हूँ कि जिस तरह से कांग्रेस गुजरात के मुख्यमंत्री और भाजपा के भावी प्रधानमंत्री थाई नरेन्द्र मोदी और भाजपा पर अनर्गल आरोप लगा रही है

वह उसके मानसिक दिवालियेपन की परिचयक है। चुनाव को प्रभावित करने की कांग्रेस की हर कोशिश विफल होगी। भाजपा किसी भी सूरत में नरेन्द्र मोदी पर पुनर्विचार नहीं करने वाली, बल्कि इन आरोपों को बेबुनियाद सिद्ध करके श्री नरेन्द्र मोदी और मजबूत होकर उभरेंगे। चुनाव में चार साल पुरानी सीढ़ी लेकर कांग्रेसी मोदी पर जो आरोप लगा रहे हैं उसमें रंच मात्र भी सच्चाई नहीं है यह सब जनता का ध्यान भटकाने की असफल कोशिश ही है।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में मुफ्त में 35 किलो चावल देने की बात कह रही है लेकिन कांग्रेसी शायद यह नहीं जानते कि छत्तीसगढ़ की जनता को बछाशी नहीं सम्मान चाहिए। छत्तीसगढ़ के लोग भले ही गरीब हों लेकिन स्वाभिमानी हैं और उन्हें मुफ्त में कोई चीज नहीं चाहिए। उन्होंने सवाल किया कि कांग्रेस बताए कि वह देश के कितने कांग्रेसी राज्यों में मुफ्त में चावल, दाल, नमक दे रही है? छत्तीसगढ़ में बढ़ रहे नक्सलवाद को लेकर कहा कि नक्सलवाद किसी राज्य की नहीं बल्कि यह एक राष्ट्रीय समस्या के तौर पर उभरी है। अन्य राज्यों की तुलना में छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद कम हुआ है। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने नक्सलवाद को चुनौती मानते हुए इसके लिये केंद्र से बार-बार सहयोग मांगा है लेकिन अपेक्षित सहयोग नहीं मिला है। देश में नक्सलवाद हो या आतंकवाद पर कार्रवाई करने के पहले सभी राज्यों को विश्वास में लेना चाहिए। ■



को तोड़ा है और इसके बाद तो कांग्रेस को सत्ता में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। नक्सलवाद और उग्रवाद, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सभी राज्यों को भरोसे में लेते हुए स्पष्ट तौर पर कार्ययोजना बनाने की आवश्यकता है।

गत 16 नवम्बर को रायपुर में श्री सिंह ने कहा कि भाजपा ने अपना प्रधानमंत्री मोदी को घोषित किया है पर कांग्रेस ने अब तक अपने प्रधानमंत्री का नाम नहीं बताया है। देश जानना चाहता

भाजपा स्पष्ट बहुमत से सत्ता में लौटेगी : वसुंधरा राजे



राजस्थान प्रदेश भाजपाध्यक्ष एवं मुख्यमंत्री पद की प्रत्याशी श्रीमती वसुंधरा राजे का मानना है कि राज्य में कांग्रेस सरकार के कुशासन से जनता त्रस्त है। भयंकर भ्रष्टाचार, विकट बेरोजगारी और महिलाओं के साथ अपराध में वृद्धि प्रमुख मुददा है। प्रदेश की जनता पूर्व की भाजपा सरकार को याद करने लगी है। चुनाव-प्रचार के दौरान भाजपा के पक्ष में सकारात्मक वातावरण बन रहा है। भाजपा स्पष्ट बहुमत से सत्ता में लौटेगी।

आगामी 1 दिसम्बर 2013 को आसन्न राजस्थान प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर श्रीमती राजे से कमल संदेश के कार्यकारी संपादक डॉ. शिव शक्ति बक्सी ने बातचीत की। प्रस्तुत है मुख्य अंश :-

विधानसभा चुनाव की घोषणा से पूर्व आपने अपने 'सुराज संकल्प यात्रा' के दौरान राजस्थान का व्यापक दौरा किया। जनता से मिले समर्थन को आप किस रूप में देखती हैं?

यात्रा के अन्त में जनता के सम्पर्क से मैंने दो निष्कर्ष निकाले हैं। एक, जिस प्रकार का लोगों में गुस्सा भरा हुआ है, उसे देखते हुए दिसम्बर के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के जीतने की संभावना दिखाई नहीं पड़ती है। और, दो, लोगों में हमने इस बात की वास्तविक भूख देखने को मिली कि उच्चतम पद पर कोई मजबूत नेतृत्व की कमान संभाले और अब यह चाहत पहले राज्य में बदलाव के रूप में परिणत हो रही है और यह भी कि श्री नरेन्द्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनें। परन्तु, अपनी दूसरी प्रमुख यात्रा में, जो राजस्थान के गांवों में हुई, उससे यही पता चलता है कि हर व्यक्ति महसूस कर रहा है कि 2008 से अब तक किसी भी प्रकार की प्रगति नहीं हुई।

भारत के बारे में ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनका पता तभी चल पाता है तब आप शहरों के वातावरण से निकलकर बाहर की यात्रा करें। हमारे निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियमित रूप

से अपने निर्वाचित क्षेत्रों का दौरा करने चाहिए। कौन से मुद्दे प्रमुख रूप से सामने आए, जनता की भाजपा से किस तरह की अपेक्षा दिख रही है?

एक युवक ने अपनी 'फेसबुक' पर लिखा "साइकिल चाहिए, पैसा ले लो, लैपटॉप चाहिए, पैसा ले लो, यह सरकार तो भीख की कटोरी हाथ में रखकर ही छोड़ेगी।"

हर व्यक्ति के लिए पैसा, पर रोजगार नहीं। लोग क्या सोचते हैं यही इसका लब्बोलुबाब है। मैं तो हैरान रह गई। पिछले पांच वर्षों में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रही। इस सरकार की प्रमुख विफलता को आप किस रूप में देखती हैं?

राजस्थान का आदमी स्वाभिमानी है। राहुल गांधी कहते हैं कि मैं आपको चार रोटी और मुफ्त दवाईयां दूंगा और आप मुझे बोट दो। इस विषय पर वे कहीं अधिक शालीन हो सकते थे। 60 वर्षों से अधिक के कार्यकाल में तुमने लोगों को गरीब बना के रख दिया। आप 'गरीबी हटाओ' के नारे को अमर बनाने में लगे रहे, परन्तु विश्व बैंक का कहना है कि भारत में 70 प्रतिशत लोग गरीब हैं।

स्वतंत्रता के 66 वर्षों बाद भी इसके लिए कौन दोषी हो सकता है? राजस्थान के लोग स्वाभिमानी हैं और उन्हें इस प्रकार की असंवेदनशीलता सहन नहीं हो सकती है।

गहलोत सरकार ने पांच वर्ष पूर्व पेंशन क्यों नहीं दी? हमने भामाशाह योजना चलाई थी और इसके लिए 800 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गई इस राशि में मैंने पहले ही 200 करोड़ रुपए स्थानांतरित कर दिए थे। आज जो श्री नंदन निलेकाणी (यूआईडीएआई) के माध्यम से कर रहे हैं, वह पहले हम कर रहे थे। राजस्थान की यह कड़ी परीक्षा थी जिसके माध्यम से इसका प्रयोग किया गया। परिवार की महिला सदस्य को एक कार्ड मिलेगा और 1500 रुपए की धनराशि उसके बचत खाते में जमा करा दी जाएगी। 30,000 रुपए की स्वास्थ्य बीमा योजना थी। जब (गहलोत सरकार ने) इस योजना को बंद किया तो सात लाख लोग पहले ही इसका लाभ उठा चुके थे। हमारा राज्य पहला राज्य था जिसने डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ स्थानांतरण) की योजना शुरू की थी।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाने के लिए यात्रा निकाली। आपकी नजर में इससे जनता में क्या संदेश गया?

पहला, उन्होंने हमारी नकल की और लोगों को अपनी ऐसी उपलब्धियां याद दिलाने की यात्रा शुरू की, जिन योजनाओं का कहीं कोई अता-पता ही नहीं था। और फिर जब इस संदेश यात्रा का अमर्यादित ढंग से समाप्त हुआ, उससे राजस्थान के लोगों का सरकार के प्रति आक्रोश साफ दिखाई देता है कि कांग्रेसियों पर से लोगों का विश्वास समाप्त हो गया है। कांग्रेस ने सरकारी कार्यक्रमों की आड़ में लगभग दो दर्जन निर्वाचन क्षेत्रों में यात्रा की जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने (उद्घाटन मंत्री) के रूप कुछ परियोजनाओं का शिलान्यास किया और कुछ दूसरे क्षेत्रों में उद्घाटन रिबन काटे। जोधपुर, पाली, भीलवाड़ा, नगौर, जैसलमेर और बाड़मेर क्षेत्रों में सरकारी समारोह किए गए तथा कुछ अन्य स्थानों पर सरकारी हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल किया गया। राजस्थान कांग्रेस शासन भयंकर भ्रष्टाचार के साथ-साथ सैक्स स्कैंडल और दंगों के कारण राष्ट्रीय समाचारों में छायी रही। इन मुद्दों का जनता पर क्या असर पड़ा है?

इससे राज्य में महिलाओं की हालत का पता चलता है, जो आज देशभर की महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों में राजस्थान दूसरे नम्बर का राज्य बन गया है। यह अत्यंत क्षोभकारी है कि जिस राज्य को महिलाओं के सम्मान के लिए

जाना जाता है, आज उसी राज्य का शासक वर्ग इस प्रकार के कार्यों में लिप्त है। कांग्रेस सरकार के कुशासन में इस प्रकार के कुकृत्यों से घोर निराशा होती है। महिलाओं के प्रति बढ़ते जा रहे अत्याचारों और अपराधों की घटना से राजस्थान इससे पहले कभी उतना कलंकित नहीं हुआ। यदि कोई भी राजस्थान की कांग्रेसी सरकार के पांच वर्ष के शासन को देखे तो हम देखेंगे कि पूर्व-केबिनेट मंत्री महिपाल मंदेरणा जेल की सलाखों के पीछे पड़े हैं, पूर्व-मंत्री रामलाल जाट ने हत्या के आरोपों पर इस्तीफा देना पड़ा और अब बाबूलाल नागर पर बलात्कार के आरोप लगे हैं।

केन्द्र की कांग्रेस नीत यूपीए सरकार के कारनामों से भी पूरे देश की जनता त्रस्त रही है। इनका कितना असर राजस्थान के चुनावों पर पड़ेगा?

मैं विकास, रोजगार और अन्य सुविधाओं का दृष्टिकोण लेकर चलती हूं। मैं बिजली, पानी, सड़क देना चाहती हूं। मैं चाहती हूं कि स्कूलों में शिक्षक हों, अस्पतालों में डाक्टर हों। हर आदमी यही बात चाहता है। हम इनसे पूरी तरह से जुड़े हैं। राजस्थान के अनेकों लोग काम के लिए अहमदाबाद जाते हैं। उन्होंने खुद वहां जाकर उस राज्य का विकास देखा है और वे सभी उम्मीद करते हैं कि यहां भी जब वापस आएं तो ऐसा ही विकास हो। आज, टेलीविजन ने सीधे ही हमें यूएस, चीन या जापान के हालात को हमारे घरों तक पहुंचा दिया है और हम चाहते हैं कि हमारा देश भी इसी प्रकार का हो।

मनमोहन सिंह की बड़ी-बड़ी चर्चाएं थीं। माना जाता था कि वह अर्थशास्त्र को भलीभांति समझते हैं परन्तु वह देश को क्या दे सकें? आज, लोग स्पष्ट हैं कि यदि आप हमें नहीं दे सकते हैं तो हमारे मन में भी आपके लिए कोई जगह नहीं है।

भाजपा को यदि प्रदेश की जनता सत्ता सौंपती है तब भाजपा तत्काल क्या कदम उठाएगी?

हम सभी अच्छी योजनाओं को चालू रखेंगे। एकबार सरकार बनाने का अवसर मिलते ही कांग्रेस या भाजपा का कोई मतलब नहीं, केवल लोगों की भलाई ही मेरा उद्देश्य होगा।

आप जनता से इस बार किस प्रकार के जनादेश की उम्मीद कर रहे हैं? सर्वे में तो भाजपा काफी आगे दिखती हैं- क्या आप दो-तिहाई का आंकड़ा पार कर पायेंगे?

मोटे तौर पर, सभी सर्वेक्षणों के उत्तरदाता कांग्रेसी सरकार के कार्य प्रदर्शन से खुश नहीं हैं। वातावरण निश्चित ही बहुत सकारात्मक है। हम स्पष्ट बहुमत से सत्ता में लौटेंगे। ■

“भाजपा सरकार ने राज्य में विकास के नये आयाम स्थापित किए”

भा

रतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि कांग्रेस के प्रति देश के जनता के मन में आकोश है आजादी के बाद 66 वर्षों तक देश में यदि किसी दल की सरकार रही है, तो वह कांग्रेस है। कांग्रेस ने देश के सामने जो चुनौतियां थीं उन्हें पहले से भी अधिक दुष्कर और गंभीर बना दिया है। जनता को अच्छी सरकार देने में कांग्रेस पूरी तरह असफल साबित हुई है।

गत 13 नवम्बर को इंदौर में श्री राजनाथ सिंह ने देश के मौजूदा हालात पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि वर्तमान प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने सर्वाधिक विदेश यात्राएं की हैं। प्रधानमंत्री देश में अपनी साख बनाने के लिए कामयाब नहीं हो पा रहे हैं तभी विदेश यात्रा कर विदेशों में अपनी साख बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा हाल ही में किये गये चीन के साथ किए गए सीमा समझौते को समझ से परे बताते हुए कहा कि इस समझौते से जो राजनैतिक लाभ मिलना था उस राजनैतिक लाभ की बजाए देश को राजनैतिक हानि हुई है।

चीन के साथ यू.पी.ए. सरकार ने Confidence Building Measures के नाम पर जो Border Defence Cooperation Agreement (BDCA) किया है उसका अनुच्छेद 6 कहता है कि सीमा पर अब भारत की सेनाएं घुसपैठ करने वाली चीनी सेनाओं को खदेड़ नहीं सकेगा। जब चीन पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि वह भारत

अच्छा शासन देने के लिए जैसी सोच चाहिए वह भारतीय जनता पार्टी के पास है, जबसे कांग्रेस आई है भ्रष्टाचार और जल, थल, नभ सर्वत्र लाखों, करोड़ों के घोटाले हुए हैं। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में यूपीए सरकार पर जितने आरोप लगे हैं शायद दूसरी सरकार पर नहीं लगे। जबकि भारतीय जनता पार्टी ने 1991 से 1998 तक एनडीए की सरकार चलाई। कोई आरोप-प्रत्यारोप एनडीए पर नहीं लगा उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार ने जनता को हाँसला और मनोबल तोड़ा है।

चीन की मौजूदा अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं का सम्मान नहीं करता तो ऐसे में उसके साथ सीमा समझौता कैसे संभव है? उन्होंने प्रधानमंत्री से स्पष्टीकरण मांगते हुए पूछा कि इतना बड़ा समझौता करने से पहले क्या प्रधानमंत्री ने देश की जनता को विश्वास में लिया। प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह को देश की सुरक्षा से जुड़े मसलों पर देश की संसद को विश्वास में लेना चाहिए।

श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अच्छा शासन देने के लिए जैसी सोच चाहिए वह भारतीय जनता पार्टी के पास है, जबसे कांग्रेस आई है भ्रष्टाचार और जल, थल, नभ सर्वत्र लाखों, करोड़ों के घोटाले हुए हैं। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र

भारत के इतिहास में यूपीए सरकार पर जितने आरोप लगे हैं शायद दूसरी सरकार पर नहीं लगे। जबकि भारतीय जनता पार्टी ने 1991 से 1998 तक एनडीए की सरकार चलाई। कोई आरोप-प्रत्यारोप एनडीए पर नहीं लगा उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार ने जनता को हाँसला और मनोबल तोड़ा है।

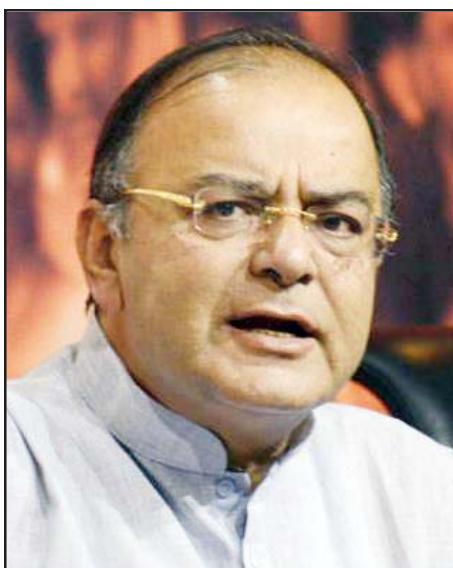
श्री राजनाथ सिंह ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के सुशासन की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने प्रदेश को बीमारू राज्यों की श्रेणी से निकालकर अग्रिम पंक्ति में लाकर खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने विकास के नये आयाम स्थापित किए हैं। उन्होंने सामाजिक सरोकारों को पूरा किया है। सभी जातियों और धर्मों के लिए शिवराज सिंह और छत्तीसगढ़ में डॉ. रमन सिंह ने जो कार्य किये हैं उसके लिए वे बधाई के पात्र हैं, सभी को न्याय और अवसर मिले हैं। केन्द्र सरकार के असहयोग के बावजूद उन्होंने राज्यों को विकसित और कल्याणकारी राज्य की श्रेणी में मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ को स्थापित किया है।

जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहा है उन 5 राज्यों की जनता से अपील करते हुए कहा कि हमारा देश संकट के दौर से गुजर रहा है, इस संकट के भंवर से देश को निकालने के लिए भारतीय जनता पार्टी को बोट दें। उन्होंने कहा कि 4 राज्यों मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और मिजोरम में भाजपा बढ़त हासिल करेगी। ■

तहलका स्कैण्डल - बलात्कार का सीधा-साधा मामला : अठण जेट्ली

त

हलका की एक महिला सहयोगी और इंटर्न जर्नलिस्ट ने 'तहलका' न्यूज मैगजीन के एडिटर-इन-चीफ पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। गोवा पुलिस ने तरुण तेजपाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। युवा महिला जर्नलिस्ट ने कहा कि उसने (तरुण तेजपाल) इस



माह गोवा के तहलका ईंवेंट के दौरान दो दिन मेरे साथ यौन-उत्पीड़न किया।

तरुण तेजपाल के खिलाफ इस यौन-उत्पीड़न के आरोप के बाद राज्य सभा में विषय के नेता श्री अरुण जेट्ली ने तीखी प्रतिक्रिया करते हुए कहा कि पीड़ित की शिकायत बलात्कार का सीधा-साधा मामला बनता है। श्री जेट्ली की इस प्रक्रिया का सम्पूर्ण पाठ नीचे प्रस्तुत है:

"भारतीय मीडिया की आज गहन परीक्षा है। एक युवा इंटर्न का आरोप है

कि एक सेवानिवृत्त जज उसकी तरफ ललचाई नजरों से अनुचित तरीके से कदम बढ़ाए। मीडिया ने इसकी व्यापक रूप से रिपोर्टिंग की। भारत के चीफ जस्टिस ने इस मुद्दे पर तीन जर्जों की कमेटी बना कर जांच बैठा दी है और अपना निष्कर्ष देने को कहा है। मीडिया का एक वर्ग भड़क उठा कि गुजरात में

पुलिस उस महिला और उसके परिवार के सहमति होने पर उसका संरक्षण करती है या माना जा रहा है कि उस पर नजर रखे हुए हैं।

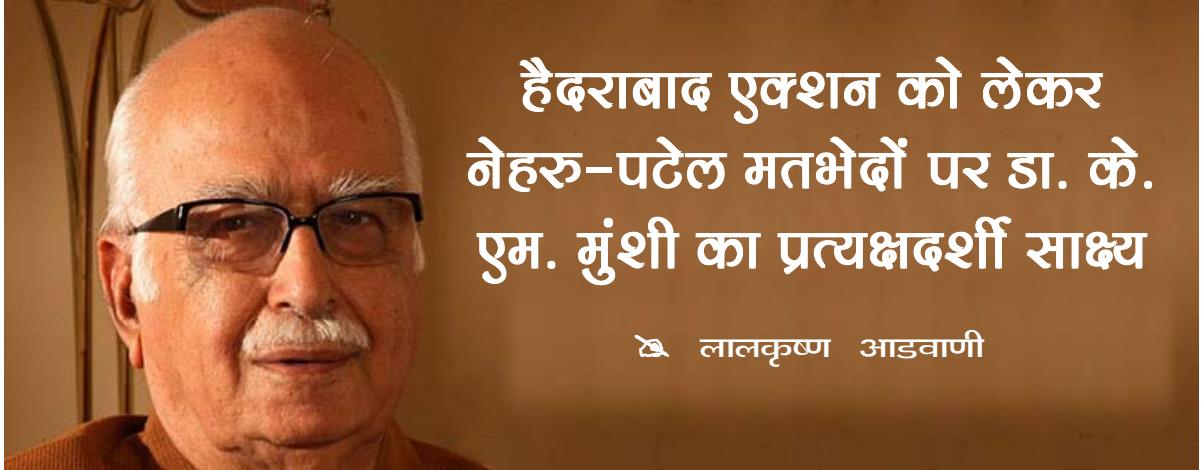
गोवा घटना में फंसे तरुण तेजपाल और युवा जर्नलिस्ट का मामला एकदम दूसरे ढंग का है। पीड़िता की शिकायत बलात्कार का सीधा-साधा मामला बनता है। जस्टिस वर्मा कमेटी की सिफारिशों के बाद संसद ने बलात्कार की परिभाषा में परिवर्तन कर दिया है। संसद के इस संशोधन के अनुसार इस अपराध के अंशों से पीड़ित ने ई-मेल में साफ-साफ लिखा है।

सवाल है कि अपराध के मामले की रिपोर्टिंग तुरन्त क्यों नहीं की गई? क्या पीड़ित पर शिकायत दर्ज न कराने का दबाव डाला गया? क्या पीड़ित पर शिकायत दर्ज न कराने का दबाव डाला गया? भला बलात्कार के अपराध में दोषी द्वारा छह महीने तक अपने ऑफिस न जाने से कैसे इसका पश्चाताप किया जा सकता है? यह कभी नहीं सुना गया कि तेजपाल और शोमा चौधरी के बीच एक निजी संधि करके बलात्कार के दण्डनीय अपराध को समाप्त किया जा

सकता है। भला शोमा चौधरी कैसे इस बात को निश्चित तौर कह सकती है कि पीड़ित पुलिस के सामने गवाही नहीं देगी? क्या वह युवा कर्मचारी पर बलात्कार अपराध छुपाने के लिए दबाव डालने का के साथ छेड़छाड़ करने की दोषी नहीं है?

दिल्ली में निर्भया के गैंगरेप के बाद सिटीजन मूवमेंट की शिकायत रही है कि यौन-उत्पीड़न के मामलों को सदा ही बहुत कम रिपोर्टिंग होती है। क्या यही इस मामले में नहीं हो रहा है? क्योंकि अपराधी के सम्बन्ध कांग्रेस पार्टी के साथ घनिष्ठ है, मात्र इस कारण देश को श्री पी चिदम्बरम की कथित सद्परामर्श, कपिल सिंबल की दिखावटी टिप्पणी और मनीष तिवारी की अतिरिंजित ट्रीटमेंट से हाथ धोना पड़ जाएगा?

हाल ही में, मनीष तिवारी गोवा में थे। उन्होंने हिटलर का पता लगा लिया। परन्तु, यह कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि वह गोवा में रहते हुए उन्हें एक सीरियल बलात्कारी का पता नहीं चल पाया। इसके अलावा, हमें यह भी देखना होगा कि क्या मीडिया इस अपराध के अनुपात के अनुसार उसका गुस्सा उस रूप में सामने आता है या नहीं? या फिर जर्नलिस्टिक दबाव इस युवा जर्नलिस्ट को सच्चाई छुपाने के लिए प्रेरित करेगा। क्या सेक्युलरिस्ट आशिकी के साथ अलग ढंग का व्यवहार किया जाएगा? हमें प्रतीक्षा करनी होगी और देखना होगा कि क्या युवा महिला सच का साक्ष्य देगी या नहीं?



हैदराबाद एक्शन को लेकर नेहरु-पटेल मतभेदों पर डा. के. एम. मुंशी का प्रत्यक्षादर्शी साक्ष्य

श. लालकृष्ण आडवाणी

गत वर्ष सरदार पटेल की जयन्ती की पूर्व संध्या यानी 30 अक्टूबर, 2012 को नई दिल्ली से प्रकाशित अंग्रेजी दैनिक पायनियर ने एक समाचार प्रकाशित किया जिसके अनुसार हैदराबाद में सेना भेजने के सरदार पटेल के फैसले के विरोध के फलस्वरूप प्रधानमंत्री नेहरु द्वारा उन पर की गई तीखी टिप्पणियों के चलते सरदार पटेल एक महत्वपूर्ण मंत्रिमंडलीय बैठक से उठकर चले गए।

तब से, विशेषकर मेरे द्वारा अपने एक ब्लॉग में पायनियर के इस समाचार का उपयोग करने के बाद से बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। निस्संदेह यह समाचार एक आइएस अधिकारी श्री एम.के.के. नायर जिनकी मृत्यु 1987 में हुई, द्वारा लिखित एक मलयालम पुस्तक पर आधारित है। जैसाकि मैंने अपने एक ब्लॉग में उल्लेख किया था कि पुस्तक का अनुवाद अंग्रेजी में हो रहा है, परन्तु अभी तक यह प्रकाशित नहीं हुई है।

लोग इस मलयालम पुस्तक के कथ्य पर संदेह उठा रहे हैं और मानते हैं कि हैदराबाद की कार्रवाई पर तथाकथित मतभेद लेखक के पूर्वाग्रह आधारित कल्पना की उपज है। वे इस तथ्य पर

जोर दे रहे हैं कि एमकेके नायर की पहुंच भारत सरकार की एक कमेटी की बैठक में होने वाली कार्रवाई तक नहीं हो सकती।

मेरे सामने 1967 में प्रकाशित डा. के.एम. मुंशी द्वारा लिखित सुव्यवस्थित दस्तावेजों पर आधारित 621 पृष्ठों की वाली पुस्तक 'पिलग्रिमेज टू फ्रीडम' है। हैदराबाद में पुलिस कार्रवाई से पूर्व

अध्याय इस विस्तृत पैराग्राफ से शुरू होता है :

"भारतीय रजवाड़ों में हैदराबाद निजाम सर्वाधिक महत्वाकांक्षी था जिसने 12 जून, 1947 को घोषित कर दिया कि "निकट भविष्य में सर्वोच्च ताकत के जाने का अर्थ होगा कि मैं एक स्वतंत्र सम्प्रभु दर्जे को फिर से पाने हेतु मेरा सक्षम होना। "उसने बेरार, जो कभी उनके राज्य का हिस्सा था, को 'वापस लेने' की मांग भी की और अपने राज्य के लिए समुद्र तक पहुंच बनाने के लिए, गोवा के बंदरगाह, लेने के लिए पुर्तगाल से बातचीत शुरू की।

श्री मुंशी भारत के एजेंट जनरल थे। इस पुस्तक में हैदराबाद में सेन्य कार्रवाई से सम्बन्धित अध्याय को मैं विस्तृत रूप से उद्धृत कर रहा हूं। यह अध्याय, घटनाक्रम में भाग लेने वाले की ओर से ठोस प्रमाण देता है तथा मलयालम पुस्तक में वर्णित घटनाओं की सत्यता को भी प्रमाणित करता है।

उनके राज्य का हिस्सा था, को 'वापस लेने' की मांग भी की और अपने राज्य के लिए समुद्र तक पहुंच बनाने के लिए, गोवा के बंदरगाह, लेने के लिए पुर्तगाल से बातचीत शुरू की।

निजाम ने अपने दिल में ब्रिटिश राष्ट्रमंडल का 'तीसरा स्वतंत्र उपनिवेश' बनने का सपना संजो लिया। समझा

जाता है क्राउन रिप्रिजेन्टिव के सलाहकार सर कोनार्ड कॉफील्ड इसके प्रयोजक थे। यह सम्भव है कि उसने स्वयं ही यह विचार पहले पहल निजाम को सुझाया हो।

लम्बी वार्ताओं के बाद हैदराबाद और भारत के बीच 29 नवम्बर 1947 को एक वर्ष के स्टैन्ड्रास्टिल समझौते पर हस्ताक्षर हुए। उस अवसर पर सरदार ने संविधान सभा में अपने वक्तव्य में यह आशा प्रकट की कि इस अवधि में हैदराबाद के स्थायी रूप से विलीनीकरण का मार्ग प्रशस्त होगा।

सरदार ने मुझे (डा. के.एम. मुंशी) हैदराबाद में भारत संघ के एजेंट-जनरल बन कर जाने को कहा क्योंकि स्टैन्ड्रास्टिल समझौते के तहत दोनों पक्षों द्वारा ऐसी नियुक्ति करनी थी। जब मैंने गांधी जी से परामर्श किया तो उन्होंने इसको अपनी स्वीकृति दी, अतः मैंने इसे स्वीकार कर लिया परन्तु बदले में कुछ भी लेने से इंकार किया।” अध्याय में आगे लिखा है:

दिल्ली में बैठे कुछ लोगों द्वारा हैदराबाद समस्या हेतु समानांतर नीतियों के चलते हैदराबाद में मेरी (डा. के.एम. मुंशी की) स्थिति काफी असहज थी क्योंकि सरदार और वी.पी. मेनन मेरे माध्यम से राज्य का विलय उन्हीं शर्तों पर कराने का प्रयास कर रहे थे जैसाकि अन्य राज्यों का किया गया था। गवर्नर जनरल लार्ड माउंटबेंटन निजाम के प्रधानमंत्री लाइक अली से बातचीत कर रहे थे, जिसे सर वाल्टर माक्टॉन का समर्थन प्राप्त था और हैदराबाद को पर्याप्त स्वायत्तता प्रदान करने हेतु तैयार थे। यदि निजाम संघ में आने हेतु एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दे।

सरदार द्वारा अपनाई गई नीति के नेहरु विरोधी थे। एक अवसर पर, सरदार को सुझाया गया कि हैदराबाद में मेरे स्थान पर किसी और को भेजा जाए। सरदार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। अनेक अवसरों पर मुझे तब हताशा हुई जब मेरे प्रधानमंत्री को मेरे पर विश्वास नहीं था, जबकि प्रत्येक समय मैंने उन्हें इतेहाद द्वारा ढहाए जा रहे अत्याचारों पर निष्पक्ष पुष्ट प्रमाण भी दिए। यदि सरदार का मुझ पर विश्वास नहीं होता तो मैं यह काम कब का छोड़ चुका होता।

सरदार द्वारा अपनाई गई नीति के नेहरु विरोधी थे। एक अवसर पर, सरदार को सुझाया गया कि हैदराबाद में मेरे स्थान पर किसी और को भेजा जाए। सरदार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। अनेक अवसरों पर मुझे तब हताशा हुई जब मेरे प्रधानमंत्री को मेरे पर विश्वास नहीं था, जबकि प्रत्येक समय मैंने उन्हें इतेहाद द्वारा ढहाए जा रहे अत्याचारों पर निष्पक्ष पुष्ट प्रमाण भी दिए। यदि सरदार का मुझ पर विश्वास नहीं होता तो मैं यह काम कब का छोड़ चुका होता।

निजाम और उसके सलाहकारों की हठधर्मिता के चलते हैदराबाद की स्थिति अनवरत रूप से टकराव की तरफ बढ़ रही थी, ऐसे में सरदार ने निजाम की सरकार को यह संदेश भिजवाना उचित समझा कि भारत सरकार की सहन शक्ति तेजी से समाप्त होती जा रही है। तदनुसार इस आशय का एक संदेश स्टेट्स मिनिस्ट्री की ओर से वी.पी.

मेनन द्वारा भेजा गया।

जब यह जवाहरलाल नेहरु को पता चला तो वह बहुत नाराज हुए। जिस दिन हमारी सेना हैदराबाद को मार्च करने वाली थी, उससे एक दिन पूर्व उन्होंने मंत्रिमण्डल की रक्षा समिति की बैठक बुलाई। इसमें तीनों सेनाध्यक्षों को नहीं बुलाया गया। यह बैठक प्रधानमंत्री के कक्ष में हुई और जवाहरलाल नेहरु, सरदार, मौलाना आजाद, तत्कालीन रक्षा और वित्त मंत्री, स्टेट सेक्रेटरी वी.पी. मेनन और रक्षा सचिव एच.एम. पटेल इसमें मौजूद थे।

विचार-विमर्श मुश्किल से शुरू हुआ ही था कि जवाहरलाल

नेहरु क्रोध में उबलते हुए आए और हैदराबाद के सम्बन्ध में सरदार की कार्रवाई और नीति पर उनको फटकारा। उन्होंने अपना गुस्सा वी.पी. मेनन के विरुद्ध भी प्रकट किया। उन्होंने अपना गुस्सा इस टिप्पणी के साथ समाप्त किया कि भविष्य में, हैदराबाद से सम्बंधित सभी मामलों में वह स्वयं उपस्थित रहेंगे। उनके हमले का आवेग, और समय ने सभी मौजूदा लोगों को सकते में डाल दिया। इस दौरान सरदार बगैर एक शब्द बोले बैठे रहे। तब वह उठे और वी.पी. मेनन के साथ बैठक से बाहर चले गए। बैठक बगैर कुछ काम किए स्थगित हो गई।

वी.पी. मेनन ने जवाहरलाल नेहरु से अपना विरोध दर्ज कराया कि यदि वे इस सम्बन्ध में ऐसी सोच रखते हैं तो स्टेट्स मिनिस्ट्री में मेरे (मेनन) बने रहने का कोई अर्थ नहीं है।

तब तक प्रधानमंत्री को महसूस हो चुका था कि उन्होंने कुछ ज्यादा ही कर

दिया है तथा उन्होंने मेनन से माफी मांगी। उन्होंने सरदार के हाथों से हैदराबाद का विभाग छीन लेने की अपनी धमकी पर कभी अमल नहीं किया, और उधर सरदार पुलिस कार्रवाई के सम्बन्ध में अपने कार्यक्रम पर टस से मस नहीं हुए। उसके बाद दोनों में फिर कभी हैदराबाद के विषय पर विचार-विमर्श नहीं हुआ।

श्री वी.पी. मेनन और एच.एम. पटेल पूर्ववर्ती घटना के की सच्चाई का अंदाजा लगा चुके थे।

पुलिस कार्रवाई शुरू होने के निर्धारित समय से थोड़ा पहले जब ब्रिटिश सेना प्रमुख ने कार्रवाई को टालना चाहा तो सरदार निर्धारित समय-सीमा पर ढटे रहे और हमरी सेनाओं ने हैदराबाद में प्रवेश किया।

तेजी से कार्रवाई हुई। जैसे ही सेना सामने आई तो निजाम की तिनके भरी सत्ता ढह गई।

वी.पी. मेनन की पुस्तक “दि इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स” के अनुसार कासिम रिजबी के एक भाषण में कहा गया था कि यदि भारत देश, हैदराबाद आता है तो उसे डेढ़ करोड़ हिन्दुओं की हड्डियों और राख के सिवाय कुछ और नहीं मिलेगा।

13 सितम्बर को सेना का ‘ऑपरेशन पोलो’ शुरू हुआ। 17 सितम्बर को ऑपरेशन समाप्त हुआ और लाइक अली तथा उनके मंत्रिमंडल ने अपने त्यागपत्र दे दिए। उसी दिन निजाम ने अपनी सेना को भारतीय सेनाओं के सम्मुख हथियार डालने को कहा। समूचे देश में एक भी साम्प्रदायिक घटना नहीं घटी।

टेलीपीस (पश्चलेख)

सैनिक कार्रवाई की सफलता के पश्चात् श्री के.एम. मुंशी ने एजेंट-जनरल के पद से त्यागपत्र दे दिया। स्टेट्स मिनिस्ट्री ने एक प्रेस नोट जारी कर मुक्त कंठ से प्रशंसा की कि कैसे मुंशीजी ने सौंपे गए काम को पूरी तर्मयता से किया।

मुंशी अपनी पुस्तक “पिलग्रिमेज टू फ्रीडम” में लिखते हैं:

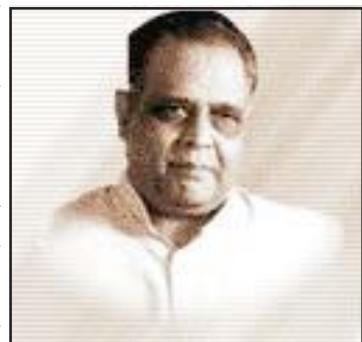
जब मैं दिल्ली लौटा तो सरदार ने आग्रह किया कि मुझे शिष्टाचार के नाते जवाहरलाल नेहरू से मिलना चाहिए। जब मैं संसद भवन स्थित प्रधानमंत्री कार्यालय गया तो वह अपने अन्तः कक्ष से बाहर आए और ठंडेपन से मुझसे मिले: “हैलो मुंशी।” मैंने कहा “मैं आप से मिलने आया था और अब मैं दिल्ली वापस आ गया हूँ।” वह लगभग ऐसे मुड़े जैसे जाने वाले हों, तब वह पीछे मुड़े हाथ मिलाया और चले गए।

मैंने सरदार को बताया कि जवाहरलाल नेहरू से भेंट की उनकी सलाह मानकर कैसे मुझे दुःख हुआ। सरदार हँसे और कहा “उनमें से कुछ तुमसे इसलिए खफा हैं कि तुमने इतेहाद की ताकत समाप्त करने में सहायता की। कुछ अन्य इसलिए गुस्सा हैं कि तुमने हैदराबाद से निजाम को सीधे हटाने नहीं दिया। कुछ अपना गुस्सा मुझ पर नहीं उतार सकते और इसलिए तुम्हें निशाना बना रहे हैं।” ■

श्रद्धांजलि

पूर्व सांसद दीनानाथ मिश्र नहीं रहे

भाजपा के पूर्व राज्यसभा सदस्य एवं पांचजन्य के पूर्व संपादक श्री दीनानाथ मिश्र का 13 नवम्बर 2013 को



निधन हो गया। वह 76 वर्ष के थे। श्री मिश्र वर्ष 1998 से 2004 तक सांसद रहे थे। उन्होंने अपना करियर पत्रकार के रूप में शुरू किया था और वह वर्ष 1971 से 1974 तक पांचजन्य के संपादक रहे थे। बाद में वे नवभारत टाइम्स के संपादक भी रहे।

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह द्वारा जारी शोक वक्तव्य

भाजपा के पूर्व सांसद, विष्ण्यात पत्रकार और व्यंग्यकार पंडित दीनानाथ मिश्र का आकस्मिक निधन से मुझे व्यक्तिगत तौर पर गहरा दुख पहुंचा है। बतौर सांसद, पंडित दीनानाथ मिश्र ने एक ईमानदार एवं कर्मठ लोक सेवक की तरह जनता को अपनी सेवाएं प्रदान कीं। साथ ही, अंतिम सांस तक उन्होंने अपनी लेखनी से पत्रकारिता को एक नई ऊर्जा प्रदान की। कई पुरस्कारों से सम्पन्नित पंडित दीनानाथ मिश्र एक विचारक उद्भृत विद्वान् एवं समर्पित पार्टी कार्यकर्ता थे। पार्टी के साहित्य सूजन एवं अन्य नीतिगत विषयों में उनका योगदान उल्लेखनीय रहा है। इनके निधन से हुए रिक्त स्थान की भरपाई होनी बेहद मुश्किल है।

मैं दिवंगत आत्मा की शांति तथा शोक की इस घड़ी में उनके परिजनों को शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। ■

मौलाना अबुल कलाम आजाद और आचार्य जेबी कृपलानी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि!

■ नरेंद्र मोदी

आ ज हम बेहद प्रेरणादायक व्यक्तियों को याद कर रहे हैं, जिन्होंने भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। हम मौलाना अबुल कलाम आजाद और आचार्य जेबी कृपलानी की 125वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। दोनों एक ही वर्ष में पैदा हुए, दोनों ही व्यक्तियों ने अपने जीवन को देश की सेवा के लिये समर्पित कर दिया।

मौलाना अबुल कलाम आजाद को किसी परिचय की जरूरत नहीं। उनके अंदर युवा अवस्था से ही क्रांतिकारी आग थी। 1912 में उन्होंने अखबार अल-हिलाल शुरू किया, जिसने कभी भी प्रवासीय शासकों पर हमला करने में झिझक नहीं दिखायी। 1940 के दशक में उन्होंने महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी में अहम भूमिका निभाई।

मौलाना अबुल कलाम आजाद को किसी परिचय की जरूरत नहीं। उनके अंदर युवा अवस्था से ही क्रांतिकारी आग थी। 1912 में उन्होंने अखबार अल-हिलाल शुरू किया, जिसने कभी भी प्रवासीय शासकों पर हमला करने में झिझक नहीं दिखायी। 1940 के दशक में उन्होंने महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी में अहम भूमिका निभाई।



वे भारत के पहले शिक्षा मंत्री हुए और उन्हों के कार्यकाल में खड़गपुर में पहला आईआईटी स्थापित किया गया। मौलाना आजाद को भारत के विभाजन का विरोध करने के लिये भी याद किया जाता है।

ऐसे व्यक्ति जिनके लिये उनके मूल्य और गरीबों की सेवा सबसे महत्वपूर्ण थे, उनका नाम है आचार्य कृपलानी जिन्होंने महात्मा गांधी के नेतृत्व में चंपारण सत्याग्रह में भाग लिया और कांग्रेस के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी।

स्वतंत्रता के बाद उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और किसान मजदूर प्रजा पार्टी में चले गये, जो बाद में सोशलिस्ट पार्टी के रूप में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी बनी।

आचार्य कृपलानी ने पंडित जवाहर लाल नेहरू की सरकार के खिलाफ 1963 में पहली बार अविश्वास प्रस्ताव

लाकर एक इतिहास रचा।

यह प्रस्ताव चीन से मिली करारी और अपमानजनक हार के बाद लाया गया, जिसमें कहा गया कि प्रथम प्रधानमंत्री और तत्कालीन रक्षा मंत्री वीके कृष्ण मेनन ने जंग के लिये कोई तैयारी नहीं की थी।

वास्तव में आचार्य कृपलानी ने लोकसभा में बार-बार बहुत सख्ती से कृष्ण मेनन का विरोध किया। उस दौर को हम नहीं भूल सकते जब वे कृष्ण मेनन के खिलाफ 1962 में उत्तर बॉम्बे से चुनाव लड़े वो भी सभी पार्टियों के ज्वाइंट कैंडिडेट के रूप में।

इमर्जेंसी के भी बो कट्टर आलोचक रहे। आचार्य कृपलानी का गुजरात विद्यापीठ से बहुत करीबी ताल्लुक रहा, जिसकी स्थापना गांधी जी ने की थी।

आज हमें उन प्रयासों की जरूरत है जो ऐसी तमाम ऐतिहासिक शख्सियतों

वारतव में आचार्य कृपलानी ने लोकसभा में बार-बार बहुत सख्ती से कृष्ण मेनन का विरोध किया। उस दौर को हम नहीं भूल सकते जब वे कृष्ण मेनन के खिलाफ 1962 में उत्तर बॉम्बे से चुनाव लड़े वो भी सभी पार्टियों के ज्वाइंट कैंडिडेट के रूप में। इमर्जेंसी के भी वो कदूर आलोचक रहे। आचार्य कृपलानी का गुजरात विद्यापीठ से बहुत करीबी ताल्लुक रहा, जिसकी स्थापना गांधी जी ने की थी।

को याद करें, जिन्हें पूरी तरह से उपेक्षित कर दिया गया या फिर इतिहास की किताबों में उनके बारे में बहुत कुछ नहीं लिखा गया।

इस ब्लॉग को पढ़ने के बाद आप टीवी स्टूडियो और सोशल मीडिया की तरफ देखेंगे तो वहाँ कमेंट्स का अम्बार लगा होगा जैसे “उनमें और मोदी में क्या समानता है” या “लेकिन वे मोदी की पार्टी में तो नहीं थे” और कई बातें।

मित्रों यहीं वो विचारधारा है, जिसमें परिवर्तन की जरूरत है।

यह सोचकर मैं बहुत व्यथित होता हूं कि हमारे मित्रों ने कुछ राजनेताओं की भक्ति में स्वतंत्रता संग्राम के बहादुरों को महत्व देना कम कर दिया है। इससे बड़ा देश का नुकसान नहीं हो सकता कि हम इतिहास को राजनीतिक पक्षपात की संकीर्ण दृष्टि से हमारे शूरवीरों को देखें।

समय है यह समझने का कि इन नेताओं ने जाति, समाज, संप्रदाय या पार्टी से ऊपर उठकर देश हित में काम किया। उनके आदर्श और विरासत किसी

पार्टी तक सीमित नहीं है बल्कि पूरा राष्ट्र उनसे प्रेरणा लेता है।

समान रूप से चिंता की बात ‘इतिहास के सट्टा (Speculative History)’ की प्रवृत्ति भी है जहाँ कुछ सेलिब्रिटी इतिहासकारों ने खुद को यह अधिकार दे दिया कि वह खुद सट्टा कर सकें जो कुछ ऐतिहासिक हस्ती ने कहा या किया होगा।

अब आप मौलाना अबुल कलाम आजाद और सरदार वल्लभभाई पटेल का ही उदाहरण ले लीजिये। हाँ यह सच है कि दोनों मौलाना आजाद और सरदार पटेल की विचारधारा कई मुद्दों पर भिन्न थी। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि दोनों ही भारत के लिये पूरे प्रेम और निष्ठा के साथ महात्मा गांधी के नेतृत्व में साथ में काम करते थे। आखिरकार जो भी तर्क-वितर्क, चर्चा और असहमति थी वह सब एक vibrant लोकतंत्र के जरूरी होती है।

हमारे प्राचीन ग्रंथों में लिखा है कि सीखना एक निरंतर प्रक्रिया है। ज्ञान और समझ समय के साथ विकसित होने चाहिये और कभी भी भूतकाल की असहमति के गर्त में खत्म नहीं हो जाने चाहिये।

इसी संदर्भ में मैं सरदार पटेल पर मौलाना आजाद के विचारों को आपके साथ बांटना चाहता हूं, जो ‘इंडिया विन्स फ्रीडम’ में प्रकाशित हुए थे। मौलाना आजाद ने कहा कि कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिये दोबारा नहीं खड़ा होना उनकी पहली गलती थी। अपनी दूसरी गलती के लिये उन्होंने लिखा:

“मेरी दूसरी गलती यह थी कि जब मैंने खुद को नहीं खड़ा करने का निर्णय लिया तब सरदार पटेल का भी समर्थन नहीं किया। कई मुद्दों पर हमारे विचार नहीं मिलते थे, लेकिन मैं इस

बात से सहमत था कि उन्होंने कैबिनेट मिशन प्लान को सफलतापूर्वक लागू किया। उन्होंने जवाहर लाल नेहरू की उस गलती को भी नहीं किया होता, जिसने जिन्होंने विद्रोही योजना बनाने का अवसर दिया। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर सकता, अगर मैंने यह गलतियाँ नहीं की होतीं तो शायद पिछले दस साल का देश का इतिहास कुछ अलग होता।”

यह बात भी उतनी ही सच है कि कई ऐतिहासिक हस्तियाँ हैं जो आम जनता के दिल और दिमाग से गायब हो गई हैं, सिर्फ इसलिये क्योंकि वो उस विशेष परिवार से ताल्लुक नहीं रखती थीं।

भारत का इतिहास अनगिनत महिलाओं और पुरुषों के संघर्ष का इतिहास है, जिन्होंने अपनी मातृभूमि के लिये अपना जीवन समर्पित कर दिया। क्या सिर्फ इसलिये हम जनता के दिमाग से उन्हें मिटा दें या कम याद करें क्यूंकि वे एक विशेष परिवार के नहीं हैं ?

केंद्र सरकार मौलाना आजाद पर आज एक पोर्टल लॉन्च कर रही है, जिसमें उनके डिजिटल पुरालेख होंगे। हम इस पहल का स्वागत करते हैं, लेकिन उनसे यह भी पूछना चाहिये कि पिछले दशकों में उन्होंने सिर्फ एक विरासत को अपनी समर्पित सेवाएं क्यों दीं? क्या यह सब पहले नहीं करना चाहिये था?

मौलाना अबुल कलाम आजाद और आचार्य कृपलानी को मैं अपनी श्रद्धांजलि इस प्रार्थना के साथ समाप्त करता हूं कि हम एक ऐसे भारत का निर्माण कर सकते हैं जिसका सपना उन्होंने और उनके जैसे स्वतंत्रता संग्राम के तमाम शूरवीरों ने देखा था। ■

(लेखक प्रधानमंत्री पद के लिए भाजपा प्रत्याशी और गुजरात के मुख्यमंत्री हैं)

किसने बदला इतिहास-भूगोल

४ बलबीर पुंज

पि

छले दिनों मुलायम सिंह यादव ने देश के विभाजन के लिए कांग्रेस को कसूरवार बताया। दूसरी ओर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भारतीय जनता पार्टी पर देश के इतिहास और भूगोल से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। वास्तव में इतिहास और भूगोल के साथ खिलवाड़ तो कांग्रेस कर रही है। भारत का एक-तिहाई

चुनावी माहौल होने के कारण मुलायम सिंह यादव अब भी देश के विभाजन में कट्टरपंथी मुसलमानों की भूमिका को नजरअंदाज करना चाहते हों, किंतु यह स्थापित सच है कि देश के रक्तरंजित विभाजन के लिए जहां मुस्लिम अलगाववाद बड़ा कारण था, वहीं उस मानसिकता को पोषित करने की कांग्रेसी नीति भी बराबर की अपराधी है। 1905 के बंग विभाजन, 1909 के मॉटे-मोर्ले रिफार्म से लेकर खिलाफत आंदोलन में कांग्रेस की जो भूमिका रही, उससे कालांतर में द्विराष्ट्र की मानसिकता और पुष्ट हुई। 1909 के इस अधिनियम, जिसमें मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग मान ली गई थी, को कांग्रेस ने मौनव्रती होकर क्यों स्वीकारा? तुर्की के खलीफा की बहाली के लिए भारत के मुसलमानों द्वारा छेड़े गए खिलाफत आंदोलन में कांग्रेस का कूद पड़ा किस दृष्टि से तर्कसंगत था? 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच हुए लखनऊ समझौते से देश को क्या हासिल हुआ? इतिहासकारों

मुलायम सिंह यादव भले ही देश के विभाजन में कट्टरपंथी मुसलमानों की भूमिका को नजरअंदाज करना चाहते हों, किंतु यह स्थापित सच है कि देश के रक्तरंजित विभाजन के लिए जहां मुस्लिम अलगाववाद बड़ा कारण था, वहीं उस मानसिकता को पोषित करने की कांग्रेसी नीति भी बराबर की अपराधी है। 1905 के बंग विभाजन, 1909 के मॉटे-मोर्ले

रिफार्म से लेकर खिलाफत आंदोलन में कांग्रेस की जो भूमिका रही, उससे कालांतर में द्विराष्ट्र की मानसिकता और पुष्ट हुई। 1909 के इस अधिनियम, जिसमें मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग मान ली गई थी, को कांग्रेस ने मौनव्रती होकर क्यों

स्वीकारा?

तुर्की के खलीफा की बहाली के लिए भारत के मुसलमानों द्वारा छेड़े गए खिलाफत आंदोलन में कांग्रेस का कूद पड़ा किस दृष्टि से तर्कसंगत था? 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच हुए लखनऊ समझौते से देश को क्या हासिल हुआ? इतिहासकारों

का मानना है कि कांग्रेस के उस समय के नेताओं ने सोचा था कि जो समझौता बन रहा है, वह अंतिम अध्याय है, परंतु वह पहला अध्याय निकला और उसके अंतिम अध्याय का नाम पाकिस्तान पड़ा।

सेक्युलरिस्ट देश के विभाजन के लिए हिंदू महासभा को कसूरवार ठहराते

हैं, किंतु सावरकर के 1937 में अखिल भारतीय हिंदू महासभा के सभापति बनने से पूर्व 19 दिसंबर, 1930 के मुस्लिम लीग के वार्षिक अधिवेशन में इकबाल ने मजहब के आधार पर अलग राष्ट्र का खाका खींचा तो 1933 में चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान की रूपरेखा निर्धारित की थी। अपनी प्रसिद्धि के चरमोत्कर्ष काल में भी हिंदू महासभा हिंदू आबादी के चार प्रतिशत हिस्से को भी अपने साथ नहीं कर सकी थी। हिंदू आबादी का अधिकांश भाग गांधीजी की कांग्रेस के साथ था। किंतु अपनी तमाम सेक्युलर कोशिशों के बावजूद कांग्रेस चार प्रतिशत मुसलमानों को भी अपनी ओर नहीं खींच पाई। वे जिना के साथ खड़े हो 'लड़के लंगे पाकिस्तान' का नारा लगाते रहे।

मुस्लिम शासकों के सात सौ साल के राज के दौरान जहां हिंदुओं को अपमानजनक परिस्थितियों में जजिया देकर या इस्लाम कबूल कर जिंदा रहने को अधिशास्त होना पड़ा, वहीं मुस्लिमों में सामंती मानसिकता विकसित हुई। यही मानसिकता देश की आजादी को लेकर उनके मन में छाई रही। ब्रितानियों के जाने के बाद उनमें यह डर था कि उन्हें उन लोगों के साथ बराबरी के स्तर पर रहना होगा, जिन पर उनके पुरखों ने राज किया है। इस मानसिकता का ब्रितानियों ने अपने हित के लिए खूब दोहन किया और हिंदू-मुस्लिम के बीच मौजूद सामाजिक खाई का लाभ उठाया।

1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दिखे हिंदू-मुस्लिम एकता के

भू-भाग 1947 के देश विभाजन की भेंट चढ़ गया। कश्मीर के एक-तिहाई हिस्से में पाकिस्तान का अवैध कब्जा है तो 62 में चीन ने भारत के 40,000 वर्ग किलोमीटर भूक्षेत्र को हथिया लिया। भारत के भूगोल को बदलने का जिम्मेदार कौन है?

चुनावी माहौल होने के कारण

उफान से ब्रितानी शासक भयभीत थे। गदर का ज्वार थमते ही बंबई के तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड एलफिन्स्टोन ने ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा गठित समिति को एक गूढ़ मंत्र भेजा था- ‘फूट डालो। और यह हमारा होगा।’ 3 मार्च, 1862 को लॉर्ड एल्जिन को भेजे पत्र में तत्कालीन राज्य सचिव चार्ल्स बुड ने लिखा है, ‘हमने एक के खिलाफ दूसरे को खड़ा कर अपनी सत्ता पुनः कायम की है, और हमें इसे निरंतर बनाए रखना होगा।’ और 10 मई को बुड ने लिखा, ‘जातियों के बीच स्वभावगत द्वेष हमारी शक्ति के लिए महत्वपूर्ण तत्व है।’

इसी पृष्ठभूमि में हमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के रूप में उभरी मुस्लिम सांप्रदायिकता को देखना चाहिए। 1857 के गदर में सैयद अहमद ने ब्रितानियों की मदद की थी। ‘सर्वाधिक विश्वासपात्र मुसलमान’ के रूप में ख्यात सैयद अहमद ने 1875 में अलीगढ़ में एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। कॉलेज की आधारशिला खुद तत्कालीन वायसराय ने रखी थी, जो

सर सैयद ने 1857 के स्वतंत्रता संघात में मुसलमानों के भाग लेने को लेकर न केवल मुसलमानों को लताड़ा, बल्कि उन्हें ब्रितानियों का साथ देने के लिए प्रेरित भी किया। उन्होंने हिंदू बनाम मुसलमान, हिंदी बनाम उर्दू और संस्कृत बनाम फारसी का मुद्दा उठाकर मुसलमानों की मजहबी भावनाओं का दोहन किया। वे हिंदू और मुसलमान को दो राष्ट्र मानते थे। 16 मार्च, 1888 को मेरठ में दिए उनके भाषण से तत्कालीन माहौल और मानसिकता को समझा जा सकता है। उन्होंने कहा था, ‘फर्ज करो कि ब्रितानी भारत में नहीं हैं तो कौन शासक होगा? क्या यह संभव है कि दो राष्ट्र, हिंदू और मुसलमान एक ही ताज पर बराबर के हक से बैठेंगे? मुस्लिम आबादी में हिंदुओं से कम हैं और अंग्रेजी शिक्षित तो और भी कम, किंतु उन्हें गौण या कमजोर नहीं समझा जाए। वे अपने दम पर अपना मुकाम पाने में सक्षम हैं। किंतु कल्पना करो कि ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा? तब हमारे मुसलमान भाई और पठान पहाड़ों से उतरेंगे और उत्तर की ओर बंगाल की आखिरी हद तक खून की नदियां बहा देंगे..जब तक एक राष्ट्र दूसरे को जीतकर अपने अधीन न बना ले, इस धरती पर शांति कायम नहीं हो सकती।’

अंततः पाकिस्तान की नींव का पथर साबित हुआ। 1954 में अलीगढ़ के छात्रों को संबोधित करते हुए आगा खां ने कहा था, ‘सभ्य इतिहास में प्रायः विश्वविद्यालयों ने देश के बौद्धिक व आध्यात्मिक जागरण में महती भूमिका निभाई है। अलीगढ़ भी अपवाद नहीं है। किंतु हम यह गौरव के साथ दावा कर सकते हैं कि स्वतंत्र संप्रभु पाकिस्तान का जन्म अलीगढ़ के मुस्लिम विश्वविद्यालय में हुआ।’

सर सैयद ने 1857 के स्वतंत्रता संघात में मुसलमानों के भाग लेने को लेकर न केवल मुसलमानों को लताड़ा, बल्कि उन्हें ब्रितानियों का साथ देने के लिए प्रेरित भी किया। उन्होंने हिंदू बनाम मुसलमान, हिंदी बनाम उर्दू और संस्कृत बनाम फारसी का मुद्दा उठाकर मुसलमानों की मजहबी भावनाओं का दोहन किया। वे हिंदू और मुसलमान को दो राष्ट्र मानते थे। 16 मार्च, 1888 को मेरठ में दिए उनके भाषण से तत्कालीन माहौल और मानसिकता को समझा जा सकता है। उन्होंने कहा था, ‘फर्ज करो कि ब्रितानी भारत में नहीं हैं तो कौन शासक होगा? क्या यह संभव है कि दो राष्ट्र, हिंदू और मुसलमान एक ही ताज पर बराबर के हक से बैठेंगे? मुस्लिम आबादी में हिंदुओं से कम हैं और अंग्रेजी शिक्षित तो और भी कम, किंतु उन्हें गौण या कमजोर नहीं समझा जाए। वे अपने दम पर अपना मुकाम पाने में सक्षम हैं। किंतु कल्पना करो कि ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा? तब हमारे मुसलमान भाई और पठान पहाड़ों से उतरेंगे और उत्तर की ओर बंगाल की आखिरी हद तक खून की नदियां बहा देंगे..जब तक एक राष्ट्र दूसरे को जीतकर अपने अधीन न बना ले, इस धरती पर शांति कायम नहीं हो सकती।’

अक्सर राष्ट्र विश्वविद्यालयों का निर्माण करते हैं, परंतु अलीगढ़ विश्वविद्यालय ऐसा है, जिसने अपनी बौद्धिक क्षमता और मानव संपदा के बल पर एक नए राष्ट्र को जन्म दिया। देश का सेक्युलर अधिष्ठान उनके इस काम को निरंतर आगे बढ़ाने में लगा है। संप्रग्र सरकार ने अलीगढ़ विश्वविद्यालय की पांच शाखाएं खोलने का निर्णय लिया है। इन सबका क्या परिणाम होगा? जो राष्ट्र इतिहास से सबक नहीं लेते, वे उसे दोहराने को अभिशप्त होते हैं।

यह मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति का प्रमाद नहीं है। सर सैयद के चिंतन को अधिकांश मुस्लिमों का समर्थन प्राप्त था और आज भी है। सर सैयद की विचारधारा देश के अधिकांश मुसलमानों और सेक्युलरिस्टों के लिए प्रासंगिक है। उन्होंने अंग्रेज सरकार और मुस्लिम समाज के सहयोग से एक अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अक्सर राष्ट्र विश्वविद्यालयों का निर्माण करते हैं, परंतु अलीगढ़ विश्वविद्यालय ऐसा है, जिसने अपनी बौद्धिक क्षमता और मानव संपदा के बल पर एक नए राष्ट्र को जन्म दिया। देश का सेक्युलर अधिष्ठान उनके इस काम को निरंतर आगे बढ़ाने में लगा है। संप्रग्र सरकार ने अलीगढ़ विश्वविद्यालय की पांच शाखाएं खोलने का निर्णय लिया है। इन सबका क्या परिणाम होगा? जो राष्ट्र इतिहास से सबक नहीं लेते, वे उसे दोहराने को अभिशप्त होते हैं। ■

(लेखक भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं।)
साभार- दै. जागरण

राहुल गांधी का विवित्र मामला

४ संध्या जैन

य दि किसी एक राजनीतिक दल में प्रधानमंत्री बनने की

आशा रखने वाले व्यक्ति को किसी अन्य युगपुरुष के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम स्थल पर उसके प्रतिद्वन्द्वी द्वारा इस्तेमाल किये गये शब्दों के साथ नवाजा जाता है, तो निश्चित रूप से कोई मुद्दा बनाया जा रहा होता है। यह कि ऐसा उस राज्य में हो जहाँ कांग्रेस का शासन है तो प्रश्न के घेरे में आने वाले व्यक्ति का निजी मुद्दा बन जाता है। भारत ने आमतौर पर कांग्रेसी वंश के राजकुमार के प्रति धैर्य का परिचय दिया है। मगर सितम्बर 2005 में जब उन्होंने पहली बार अलिखित शब्द बोले, (जिसका दोष तहलका ने अपने सिर लिया था) तभी यह स्पष्ट हो गया था कि वो राष्ट्र के भाग्य विधाता नहीं हैं।

तब वो 34 वर्ष के थे। उनके साक्षात्कार को स्मरणीय बनाया उनके इस दावे ने कि वो 25 वर्ष की अवस्था में ही प्रधानमंत्री बन सकते थे (इस तथ्य की अनदेखी करते हुए कि उस समय कांग्रेस अल्पमत में थी और उसके सहयोगी दलों द्वारा एक नौसिखिये का समर्थन किया जाना सम्भव नहीं था)। अमेठी साक्षात्कारकर्ता से बातचीत करते हुए, श्री गांधी ने कहा कि उत्तर प्रदेश और बिहार की यात्रा करते समय प्रशासन जैसा कुछ नहीं नजर आता यानी प्रशासनिक व्यवस्था पूर्ण रूप से धराशायी हो गयी है। उन्होंने कहा, कांग्रेस मुलायम सिंह सरकार को समर्थन देना जारी नहीं रख सकती, 'मैं इस संबंध में कुछ

करूंगा।' संप्रग-2 तक हिचकियां लेने के बावजूद रिश्ता कायम रहा।

मगर जैसा कि उन्होंने पहले तब कहा, वो मुलायम सिंह यादव और लालू प्रसाद को समर्थन देने में सहज नहीं महसूस करते, लेकिन पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने निर्णय लिया था। यह देखना आसान है कि साक्षात्कार को नकारना क्यों पड़ा। पश्चदृष्टि डालकर यह भी देखा जा सकता है कि सितम्बर 2013 को प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में व्यक्ति

सहायता पर निर्भर करता है... मुझे आश्चर्य हुआ कि इस व्यक्ति को क्या समझा है। विकास किस तरह सहायता पर निर्भर हो सकता है? तब उसने मुझे स्पष्ट किया। उसने उसे छोटे-छोटे तथ्यों में विभाजित कर मुझे दिखाया कि मदद कितनी महत्वपूर्ण होती है... कैसे मैं ऐसा ही कुछ भारत में प्राप्त करने जा रहा हूँ?

'जैसा कि सर्वज्ञात है नवंबर 2008 में भयावह कमांडो हमले के तुरंत बाद, आज के कददावर नेता 1 दिसंबर 2008

भारत ने आमतौर पर कांग्रेसी वंश के राजकुमार के प्रति धैर्य का परिचय दिया है। मगर सितम्बर 2005 में जब उन्होंने पहली बार अलिखित शब्द बोले, (जिसका दोष तहलका ने अपने सिर लिया था) तभी यह स्पष्ट हो गया था कि वो राष्ट्र के भाग्य विधाता नहीं हैं।

किये गये उनके उद्गार उस अध्यादेश की भर्त्सना करते हुए, जो लालू यादव को संसद सदस्यता के अयोग्य घोषित होने से बचाने के लिये लाया गया, दोनों नेताओं में से एक या दोनों को पहला मौका मिलने पर दरकिनार करने की गहन आकांक्षा की पुष्टि करते हैं। भावी सहयोगी दल निःसंदेह इस विश्वसनीयता कारक को ध्यान में रखेंगे।

अपनी हैम्बर्ग यात्रा के समय, उन्होंने कहा, 'जब मैं अन्य देशों के लोगों से मिलता हूँ, तो वो मुझसे हमारी समस्याओं के बारे में पूछते हैं। मैं सोचता हूँ कि यदि वे मुझसे इस बारे में पूछ रहे हैं, तो हमारे काम करने के तरीकों में कुछ गड़बड़ हैं।... मैं आपको हैम्बर्ग में अपने अनुभवों में से एक बताऊंगा। वहाँ पर यह छोटे से देश का राष्ट्रपति था... उसने मेरी ओर देखा और कहा कि सब कुछ

को कैप्टन सतीश शर्मा के बेटे के विवाहपूर्ण समारोह की पार्टी में शामिल हुए जो दिल्ली फारमहाउस में आयोजित की गई थी। उसके कुछ दिनों बाद विवाह संपन्न हुआ, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत संपूर्ण गांधी परिवार ने भाग लिया। मुंबई में बहुत से प्रख्यात परिवारों ने मरने वाले लोगों के सम्मान में ऐसे ही बहुत से समारोह निरस्त कर दिये।

और पाकिस्तान प्रायोजित उस हमले के कुछ महीनों बाद, श्री गांधी ने एक अमेरिकी दूत टिमोथी रोमर को बताया कि 'उग्र हिंदू समूहों का बढ़ना भारत के लिये बड़ा खतरा हो सकता है, जो मुस्लिम समुदाय के भीतर धार्मिक तनाव एवं राजनीतिक टकराव पैदा करते हैं' (विकीलीक्स के मुताबिक)। अवसर था प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा जुलाई

2009 में भारत आयी अमेरिकी विदेश सचिव हिलेरी क्लिंटन के सम्मान में आयोजित किया गया थोज। श्री रोमर ने भारत के भीतर मुस्लिम समुदाय के कुछ तत्वों द्वारा समर्थन दिये जाने के आलोक में लश्करे तैयबा के खतरे के बारे में पूछा। वो निश्चित रूप से भौंचकके रह गये होंगे जब श्री गांधी ने भाजपा में मौजूद गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी जैसे अधिक धृतीकरणकारी व्यक्तियों को लेकर अधिक चिन्ता व्यक्त

आय स्रोतों को विविधता प्रदान की है और उनका इस्तेमाल अपने नौ बच्चों के पालन पोषण के लिये किया। नाभिकीय ऊर्जा कला की मुख्य फसल के तौर पर काम करती है...।'

मई 2009 के बार विधानसभा चुनावों ने, जहां कांग्रेस उनके नेतृत्व में मात्रा चार सीटें जीत सकी, उनकी चमक को काफी फीका कर दिया। कांग्रेस और उनका 2012 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में पतन निश्चित था

कांग्रेस उपाध्यक्ष की समस्याओं में से अधिकतर यह है कि लोग उनकी अद्वितीय बौद्धिकता से तालमेल नहीं बिछा पाते। मार्च 2009 में भारत-अमेरिका नाभिकीय सौदे पर बोलते हुए, उन्होंने कहा, 'मैंने दो गरीब परिवारों के बारे में बोला- उनमें से एक थी श्रीमती कला। श्रीमती कला ने कहा कि उन्होंने अपने आय स्रोतों को विविधता प्रदान की है और उनका इस्तेमाल अपने नौ बच्चों के पालन पोषण के लिये किया। नाभिकीय ऊर्जा कला की मुख्य फसल के तौर पर काम करती है...।'

की।'

शायद ये विचार श्री गांधी और कांग्रेस के प्रभुत्व में चलने वाली केन्द्र सरकार के लिये मायने रखते हैं जो उस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रति सामान्य शिष्टाचार दिखाने में भी विफल रही जब उसका लागभग संपूर्ण राष्ट्रीय एवं राज्य नेतृत्व 27 अक्टूबर को पटना रैली में की गई बम धमाकों की साजिश के चलते खतरे में था। अन्य वरिष्ठ नेता भी शिष्टाचार का ऐसा उल्लंघन करने के दोषी हैं।

कांग्रेस उपाध्यक्ष की समस्याओं में से अधिकतर यह है कि लोग उनकी अद्वितीय बौद्धिकता से तालमेल नहीं बिछा पाते। मार्च 2009 में भारत-अमेरिका नाभिकीय सौदे पर बोलते हुए, उन्होंने कहा, 'मैंने दो गरीब परिवारों के बारे में बोला- उनमें से एक थी श्रीमती कला। श्रीमती कला ने कहा कि उन्होंने अपने

जहां कांग्रेस को सिर्फ 28 सीटें मिलीं। इस बीच, श्री गांधी को नवंबर 2010 में दरभंगा के एलएन मिश्र विश्वविद्यालय में छात्रों के साथ आयोजित एक सभा को छोड़कर जाना पड़ा जब उन्होंने बताया कि उन्हें गुजरात के बजाय बिहार को बदलना होगा यदि वे भारत को बदलना चाहते हैं। उनकी काफी भद्र हुई और उनसे कांग्रेसशासित महाराष्ट्र में बिहारियों से होने वाले सौतेले व्यवहार के बारे में सफाई देने को कहा गया।

मई 2011 में, अपनी नव प्रसिद्ध शूट एंड स्कूट राजनीति के अंश के तौर पर, श्री गांधी ने उत्तर प्रदेश सरकार के गिलाफ भट्टा परसौल में भूमि अधिग्रहण के मुआवजे को लेकर किसानों के आंदोलन का लाभ उठाने का प्रयास किया और दावा किया कि वहां पर रख के 74 फेर हैं जिनके नीचे लाशें दबी हुई हैं, और आगे जोड़ा कि इन गांवों में

महिलाओं के साथ बलात्कार हुए थे। वह ढेर वस्तुतः गोबर का ढेर निकला और बलात्कार की बातों को दबा दिया गया। उसी वर्ष, वो लोकपाल मुद्रे को लेकर संसद की बहस में कूद पड़े और दावा किया कि लोकपाल को संवैधानिक दर्जा दिये जाने की उनकी सलाह परिवर्तनकारी होगी। अगले दिन वो दिखायी नहीं दिये और, शेष इतिहास है। सर्वाधिक याद करने योग्य था उनके द्वारा सितम्बर 2013 में बंगाली युवाओं से राजनीति में आने का आहवान क्योंकि 'राजनीति सभी जगह है। यह आपकी कमीज में हैं, पैंटों में हैं।' फिर, 'यदि भारत कम्प्यूटर है तो कांग्रेस डिफाल्ट कार्यक्रम है। कांग्रेस नैसर्जिक रूप से भारत के आंतरिक पहलू में हैं।'

इन सबसे ऊपर इलाहाबाद में इस वर्ष अगस्त में दिये गये धर्म उपदेश (संस्कृति, गहरा होता लोकतंत्र एवं अति सीमांतीकृत समुदाय), 'गरीबी एक मानसिक दशा है। इसका अर्थ खाने, पैसे और भौतिक वस्तुओं का अभाव नहीं है। यदि किसी में आत्मविश्वास है तो वह गरीबी से निजात पा सकता है।'

विंडना यह है कि उनके प्रतिद्वंद्वी ने काफी कुछ किया है- गरीबी और दुर्बलता से आत्मविश्वास के बल पर निजात पाना- और श्री गांधी के साथ ऐसा नहीं रहा। फिर भी भाजपा के पीएम पद के उम्मीदवार ने वह काम किया है जो शहजादे ने भारतीय उद्योग महासंघ से करने को कहा- सड़कें बनाना जिन पर सपने चल सकें, बिना गड्ढों की सड़कें, बड़ी सड़कें क्योंकि वे मजबूत लोगों, व मजबूत ताकतों को ढोने जा रही हैं। आशा है कि यह श्री गांधी के लिये सांत्वना होगी। ■

(साभार- पायनियर)

भारत निर्माण का असली चेहरा

४ शशांक द्विवेदी

पि छले दिनों भुखमरी मापने वाले सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स (जीएचआई) ने 2011-2013 की रिपोर्ट में भारत को भुखमरी के शिकार लोगों के मामले में 63वें स्थान पर रखा है। जबकि, श्रीलंका 43वें, पाकिस्तान 57वें, बांग्लादेश 58वें नंबर पर है। इस सूची में चीन छठे नंबर पर है। दुनिया में भुखमरी के शिकार जितने लोग हैं, उनमें से एक-चौथाई लोग सिर्फ भारत में रहते हैं। भुखमरी के मामले में हमारे हालात पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे मुल्कों से भी कहीं ज्यादा खराब हैं। भारत को इंडेक्स ने अलार्मिंग कैटिग्री में रखा है। इस सूची में भयानक गरीबी झेलने वाले इथोपिया, सूडान, कांगो, नाइजर, चाड और दूसरे अफ्रीकी देश शामिल हैं। हैरतअंगेज तथ्य यह है कि देश में 5 साल से कम उम्र के 40 प्रतिशत बच्चे अब भी कुपोषित हैं।

जीएचआई की रिपोर्ट के मुताबिक, 2011-13 में दुनिया में भूख से पीड़ित लोगों की कुल संख्या 84 करोड़ 20 लाख है। इनमें से 21 करोड़ लोग यानी एक-चौथाई के लगभग लोग अकेले भारत में हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, भारत की हालत पहले से भले ही थोड़ी बेहतर हुई हो लेकिन कई पड़ोसी मुल्कों से बदतर है। विकसित देशों की बात जाने भी दें तो पाकिस्तान और बांग्लादेश से ज्यादा भुखमरी हमारे देश में है।

यह रिपोर्ट इंटरनेशनल फूड पालिसी रिसर्च इंस्टिट्यूट और दो एनजीओ वेल्थ हंगर लाइफ और कंसर्न वर्ल्ड वाइड ने

मिलकर तैयार की है। रिपोर्ट के लिए 120 विकासशील देशों पर स्टडी की गई। स्टडी के प्रमुख मापक देश की कुल जनसंख्या में कुल कुपोषित लोगों का प्रतिशत, 5 साल से कम उम्र के कुल बच्चों में कुपोषित बच्चों का प्रतिशत और 5 साल से कम उम्र के बच्चों में मृत्यु दर रहे।

देश में लगातार बढ़ती महंगाई के बावजूद केन्द्र सरकार कह रही है कि उसके कार्यकाल में गरीबों की संख्या पहले के मुकाबले लगभग आधी हो गई है। जबकि पिछले दिनों की वर्ल्ड बैंक ने भारत में गरीबी के बारे जो अंकड़े पेश किए हैं, वें आंखें खोलने वाले हैं। संस्था के आकलन के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली आबादी के प्रतिशत के लिहाज से भारत की स्थिति केवल अफ्रीका के सब-सहारा देशों से ही बेहतर है। बैंक की वर्लोबल इकनामिक प्रास्पेक्ट्स शीर्षक से जारी रिपोर्ट भारत के शाइनिंग इंडिया के वीछे की हकीकत दिखाती है। बैंक ने अनुमान जताया है कि 2015 तक भारत की एक-तिहाई आबादी बेहद गरीबी में अपना गुजारा कर रही होगी।

कर रही होगी।

भारत में लगातार बढ़ रही महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। शिक्षा, चिकित्सा जैसी मूलभूत सुविधाएं भी उसकी पहुंच से दूर हो गयी हैं। देश में हर स्तर पर भ्रष्टाचार व्याप्त है जिसकी वजह से सरकारी सुविधाओं का

फायदा भी ठीक तरह से आम लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। सरकार और योजना आयोग किन कागजी अंकड़ों के जरिए विकास के दावे करता है, ये तो सिर्फ वही जाने असल तस्वीर कुछ और ही है। देश में आर्थिक उदारीकरण के बाद एक तबके का जबरदस्त विकास हुआ है जबकि दूसरा तबका पिछड़ता

गया। वर्तमान आर्थिक नीतियों और उदारीकरण के कारण देश के 17 फीसदी लोग करोड़ों रुपए और अपार संपत्ति के मालिक बन गए, जबकि बड़ी आबादी गरीबी में जीवन बसर कर रही है। उसे न तो भरपेट मिल रहा है और न न्यूनतम मजदूरी।

विश्व बैंक की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार विश्व के कुल गरीब लोगों में से 33 प्रतिशत सिर्फ भारत में ही रहते

प्रतिदिन की आमदनी पर गुजारा करते हैं। भारत में गरीबों की परिस्थितियां इतनी बुरी हैं कि इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। इन्हीं स्थितियों के कारण संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ने अपनी 2013 की मानव विकास रपट में भरत को दुनिया के 186 देशों में 136वें नंबर पर रखा है। तेज आर्थिक विकास का दावा करने वाला भारत आज गरीबी के धरातल पर अफगानिस्तान, बांग्लादेश, कंबोडिया, किर्गिजिस्तान, लाओस, पाकिस्तान, नेपाल, ताजिकिस्तान, उज्बेर्किस्तान, वियतनाम और यमन के समकक्ष है। इनमें से भी वियतनाम और उज्बेर्किस्तान देश मानव विकास सूचकांक के कई मामलों में भारत से बेहतर हैं।

भारत में गरीबी उन्मूलन और विकास की केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की संख्या 225 से भी ज्यादा है। केवल ग्रामीण विकास और कृषि के क्षेत्र में ही 100 से ज्यादा योजनाएं हैं लेकिन

आजादी के 60 साल बाद भी देश की एक-तिहाई आबादी गरीबी रेखा के नीचे गुजारा कर रही है। चार साल पहले भारत में नौ खरबपति थे। अब 56 हैं। बारह साल पहले भारत के सकल घरेलू उत्पाद में खरबपतियों का हिस्सा दो फीसदी था। अब बढ़कर यह 22 फीसदी

हो गया है। खेती पर निर्भर देश की 65 फीसदी आबादी का जीडीपी में हिस्सा घटकर 17 फीसदी हो गया। आर्थिक विकास के इस दर्शन ने धनी और गरीब, कृषि एवं उद्योग के बीच के अंतर को बढ़ाया है। इससे गावों और शहरों के बीच की भी खाई चौड़ी हुई है। तीन-चार साल के अन्दर-अन्दर चीजों के दाम आसमान छूने लगे हैं। हर चीज पचास से सौ-दो सौ प्रतिशत मूल्य वृद्धि कर चुकी है (केवल किसानों की उपज और मजदूरों की मजदूरी छोड़ कर)। आम आदमी की हालत खराब है। महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है।

अपने पड़ोसी देशों से भी ज्यादा भुखमरी की स्थिति होना किसी भी देश के लिए शर्मनाक है। देश में कई लाख करोड़ के घोटालों ने भ्रष्टाचार के मामले में विश्व कीर्तिमान बना दिया है जिसकी वजह से राजकोषीय घाटा बढ़ता जा रहा है। आज देश में हालात ऐसे हैं कि आम आदमी की सुनने वाला कोई नहीं है। सरकारी विभागों में लालफीताशाही इतनी हावी है कि आम आदमी अपने छोटे-छोटे कामों और दो वक्त की रैटी के लिए दर-दर भटकता रहता है। केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं पर गरीब को कभी सही प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता और अधिकांश योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती हैं।

देश में दिख रहा कागजी और तथाकथित विकास किसके लिए है और किसको लाभ पहुंचा रहा है, यह एक बड़ा विचारणीय प्रश्न है हम सबके सामने, क्योंकि सच तो यह है कि देश के अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक सभी वर्ग के लिए फिलहाल दो वक्त की रोटी जुटा पाना ही उसके जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। ■

(साभार- दै. ट्रिव्यून)

हैं। देश में हर वर्ष 25 लाख से ज्यादा लोग भूख से मरते हैं। औसतन 7000 लोग रोज भुखमरी के शिकार होते हैं। संसार में भुखमरी से मरने वाले लोगों में भारत पहले स्थान पर है। देश में 20 करोड़ से ज्यादा लोग रोज रात भूखे सो जाते हैं। 45 करोड़ भारतीय 20 रुपए